साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-28 अंक- 34 22 - 28 अगस्त 2021 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

ऑनलाइन शिक्षा और चुनौतियाँ पृष्ठ-6

अवसरवाद का पर्याय बन गई है राजनीति पृष्ठ-7

पिछले कुछ महीने में उच्चतम न्यायालय के

अहम फैसले

न्यायालय की गरिमा को बचाने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे?

मुख्य न्यायाधीश श्री. एन.वी. रमन्ना के अध्यक्षीय दौर के पहले कुछ माह में उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए जो फैसले दिए हैं, वह बहरहाल न्यायालय के प्रति आम आदमी के विश्वास को पुख़्ता करते है।

भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के चार स्तंभ माने जाते हैं यह चारों विभाग अपनी-अपनी जगह आज़ादी और लोकतंत्र की रक्षा और मज़बूती के लिए काम करते रहे हैं। फिर भी जब से देश पर आर.एस.एस. की सियासत के असर का बोलबाला हुआ है, उस समय से यहां हिटलरशाही ने भी अपने पांव जमाने शुरू कर दिये हैं और हिटलर ने जर्मनी में फासिज़्म फैलाने के लिए जिस तरह उन तमाम विभागों का प्रयोग क्या था, आर.एस.एस. का आइडियल ही हिटलर को माना जाता है, उसके रास्ते पर चलते हुए न केवल कार्यपालिका और विधायिका पर अपना कब्ज़ा कर लिया था बल्कि न्यायापालिका और मीडिया पर भी उसने भरपूर असर होने की कोशिश की। जहां तक कार्यपालिका का संबंध है आज नीचे से ऊपर तक तमाम बड़े पदों पर आर.एस.एस. के प्रशिक्षित अधिकारी बैठा दिए गए हैं, विधायिका को देखें तो केन्द्र के अलावा डेढ़ दर्जन से अधिक राज्यों पर उसके राजनैतिक अंग भाजपा का कब्ज़ा है और मीडिया तो उसका भोपूं ही बना हुआ है और कुछ सालों की अगर न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर नज़र डालें तो उसके अधिकतर फैसले संघ के नज़रिये के मुताबिक सामने आते रहे हैं। फिर भी यह बात प्रसन्नता योग्य है कि बीते कुछ माह से जब से उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर एन.वी. रमन्ना जी आए है एक हल्की सी उम्मीद नज़र आने लगी है कि शायद वह न्यायालय की प्रतिष्ठा और उसकी शान को बचाने का इरादा रखते हैं।

अभी हाल ही में उन्होंने देश के नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के संबंध से जो फैसले सुनाए हैं वह उसकी एक ताज़ा मिसाल है। और जिन से सर्वोच्च न्यायालय के नये मिजाज़ का अच्छी तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

देश की शीर्ष अदालत नागरिकों से जुड़े मूल अधिकारों के संरक्षण को लेकर निरंतर रूप से अपनी प्रतिबद्धता दिखाती आई है। वहीं राज्य और उनकी पुलिस आतंक विरोधी क़ानूनों की आड़ में ऐसे फैसले लेने पर तुली है, जिनसे लोगों का जीवन जोखिम में पड़ रहा है। इस सिलसिले में यदि मुख्य न्यायाधीश एन॰ वी॰ रमना सहित कुछ न्यायाधीशों की हालिया टिप्पणियों पर ग़ौर करें तो प्रतीत होता है कि राजनीतिक विरोधियों को आतंकित करने और आलोचकों को ख़ामोश करने के लिए राज्य सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून यानि रासुका और ऐसे अन्य क़ानूनों का और उपयोग नहीं कर पाएंगी। इतना ही नहीं कोरोना महामारी जैसी आपदा के बीच शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकारों के ऐसे फैसलों पर आंखें नहीं मूंदे रहेगी, जिनके ज़रिये सरकारें किसी वर्ग की धार्मिक या अन्य भावनाओं का तुष्टीकरण करने में लगी हों। तमाम हाईकोर्ट भी हाल में संकेत दे चुके हैं कि अगर सरकारों ने अपनी कार्यशैली न बदली तो अदालतें मूक दर्शक नहीं बनी रहेंगी। बीते दिनों मणिपुर में एक एक्टिविस्ट की रिहाई के निर्देश से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कावड़ यात्रा को लेकर सख़्ती और बकरीद से पहले केरल सरकार को देर से ही सही, तगड़ी लताड़ लगाना अदालत के नए मिजाज़ और तेवरों को दर्शाता है।

इस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के एक एक्टिविस्ट इरेंद्रो लिचोबाम की तत्काल रिहाई के आदेश दिए। लिचोबाम को मणिपुर सरकार ने रासुका के तहत गिरफ्तार किया था। दरअसल उन्होंने कोविड-19 से हुई मणिपुर के भाजपा अध्यक्ष की मौत को गाय के गोबर और गोमूत्र से जोड़कर फेसबुक पर एक टिप्पणी लिखी थी। लिचोबाम ने लिखा था कि कोरोना का उपचार गोबर या गोमूत्र में नहीं, बल्कि विवेक और विज्ञान में निहित है। इस पोस्ट के बाद वह गिरफ्तार कर लिए गए और करीब दो महीने जेल में रहे। मीडिया में आई ख़बरों के अनुसार जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष

बाक़ी पेज 11 पर

मुख्य न्यायाधीश की हैसियत से जस्टिस रमना के कुछ अहम फैसले और टिप्पणियाँ

1. सी.बी.आई. चीफ के सलेक्शन का मामला (25 मई 2021) :-

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमना के समय पर हस्तक्षेप ने सरकार, सी.बी.आई. और न्यायपालिका को एक बड़े विवाद में उलझनें से बचा लिया था, मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप के बाद ऐसे दो अधिकारी सी.बी.आई. चीफ के पद की दौड़ में बाहर हो गए थे, जिन्हें सरकार की पहली पसंद समझा जा रहा था। उनमें से एक राकेश अस्थाना थे जो सी.बी.आई. के स्पेशल डायरेक्टर के पद पर काम कर चुके थे और बाद में जिन्हें दिल्ली का पुलिस कमीशनर बनाया गया था जबकि दूसरे उस समय एन.आई.ए. के डायरेक्टर वाई.एस. मोदी थे एक क़ानून के अनुसार सी.बी.आई. के पद पर किसी ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो सकती जो नियुक्ति के 6 माह के भीतर ही रिटायर होने वाला हो।

2. देशद्रोह का मामला (16 जुलाई, 2021) :-

देशद्रोह के क़ानून का प्रयोग अंग्रेजी सरकार के दौर में स्वतंत्रता संग्राम को दबाने और विरोध के स्वर को दबाने के लिए होता था, महात्मा गांधी, गोखले और तिलक पर भी उसकी धाराओं को लगाया गया था, क्या सरकार आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी इस क़ानून को बनाए रखना चाहता है? इस क़ानून के तहत सज़ा भी बहुत कम होती है, इसके बावजूद मामलात में तफ्तीश करने वाले अधिकारियों से जवाब नहीं मांगा जाता जबकि यह बहुत आवश्यक है। इस क़ानून के ग़लत प्रयोग की बहुत सी वजहें हैं और मिसालें मौजूद हैं। यह क़ानून किसी भी ऐसे व्यक्ति को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिस से हुकूमतें वक्त या जांच एजेंसियां विरोध करती हैं। ऐसे में न सरकार को रोका जा सकता है और न जांच एजेंसी से अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो पाती है बल्कि जब तक प्रभावित व्यक्ति बेगुनाह साबित होता है, उसकी ज़िन्दगी का बहुत बड़ा कीमती समय बर्बाद हो चुका होता है। इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि इस क़ानून की देश को क्या ज़रूरत है।

3. पेगासस जासूसी मामला (05 अगस्त, 2021) :-

पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से जासूसी कराए जाने के आरोपों में अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो यह आरोप बहुत गंभीर और संगीन है। हम यह नहीं कह सकते कि सबूतों में कुछ नहीं है। इसी तरह हम यह भी नहीं कह सकते कि कुछ अपीलकर्ता इससे प्रभावित नहीं हुए हैं।

4. जजों का संरक्षण और उनकी सुरक्षा का मामला (6, अगस्त, 2021) :-

न्यायाधीशों को कोई आज़ादी नहीं दी जाती, जब जज सी.बी.आई. और आई.बी. से शिकायत करते हैं तो भी जजों की मदद के लिए आगे नही आते। यह एक गंभीर मामला है जिसे मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूं, कुछ मामलात में जिनमें गैंगस्टर और हाई प्रोफाइल अपराधी लिप्त है, वह जजों को जिस्मानी और मानसिक हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग जिन्हें उनकी पसंद का फैसला नहीं मिलता वह जजों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं।

तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्ज़े से इतनी ख़ौफ में क्यों है दुनिया?

पूरी दुनिया मौन होकर देखती रह गई और अफग़ानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथ में चला गया। 15 अगस्त 2021 की सुबह जब भारत में लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब तालिबान के लड़ाके अफग़ान राजधानी काबुल पर घेरा डाल रहे थे और अफग़ान नागरिकों की आज़ादी पर कब्ज़ा पक्का कर रहे थे। 03 महीनों से जारी लड़ाई में कंधार, हेरात, कुंडूज, जलालाबाद बल्क समेत अफग़ानिस्तान के बाकी हिस्से 1-1 कर तालिबान के कब्ज़े में आते चले जा रहे थे, लेकिन राजधानी काबुल में इतनी जल्दी हलचल मचने वाली है, इसका अंदाज़ा शायद ही किसी को था।

बीती 15 अगस्त 2021, की सुबह तालिबान के लोगों ने अचानक क़ाबुल पर घेरा डाला और अफग़ान सरकार और सेना बिना मुक़ाबला किए सरेंडर करती दिखी। इस बीच, अमेरिकी डिप्लोमैट्स को आनन-फाननन में काबुल से ले जो हेलिकाप्टर की तस्वीर भी पूरी दुनिया ने देखी।

मशीनगनों, रॉकेट लाँचर से लैस तालिबान लड़ाके काबुल शहर को घेरते चले गए। बगराम एयरबेस, बगराम `ेल पर तालिबान ने कब्ज़ा जमा लिया। काबुल शहर के एंट्री गेट और आसपास के कई अहम इमारतों को एक-एक कर तालिबान लड़ाके कब्ज़ाते चले गए और शाम होते-होते अफग़ान राष्ट्रपति अशरफ ग़नी के देश छोड़कर जाने की ख़बर भी पुख़्ता हो गई।

इसके बाद तालिबान के प्रवक्ता ने ऐलान कर दिया कि हमारे लड़ाके शहर में घुसकर क़ानून व्यवस्था और पुलिस चौकियों को संभालने जा रहे हैं। तालिबान ने हालांकि सेना और आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया कि किसी से बदला नहीं लिया जाएगा फिर भी अफरा-तफरी का माहौल दिखा, कई लोग काबुल छोड़कर जा रहे थे।

बाक़ी पेज 11 पर

नक़दी से भरे हेलिकाप्टर में क़ाबुल से भागे अशरफ़ ग़नी

अफग़ानिस्तान से भागते हुए राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी ने अपने हेलिकॉप्टर में ठूंस-ठूंस कर नक़दी भरी, इसके बावजूद जगह की कमी के कारण नोटों से भरे कुछ बैग रनवे पर ही रह गए। इस आशय की जानकारी रूस की आधिकारिक मीडिया में आई। काबुल पर तालिबान के कब्जे के साथ ही अमेरिका समर्थित ग़नी सरकार गिन गई और राष्ट्रपति सामान्य लोगों की तरह देश छोड़ने पर मजबूर हो गए।

इस बीच फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर अफग़ानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी ने कहा है कि वह काबुल छोड़कर इसलिए चले जा रहे हैं ताकि वहां खूंन ख़राबा और बड़ी मानवीय त्रासदी न हो। उन्होंने तालिबान से कहा कि वह अपने इरादे बताए और देश पर उसके कब्ज़े के बाद अपने भविष्य को लेकर अनिश्चय की स्थिति में आए लोगों को भरोसा दिलाए। काबुल स्थित रूसी दूतावास का हवाला देते हुए रूस की सरकारी समाचार एजेंसी 'तास' ने खबर दी कि 72 वर्षीय राष्ट्रपति ग़नी नकदी से भरा हेलिकॉप्टर लेकर काबुल से निकल चुके हैं। दूतावास के एक हवाले से एक कर्मचारी के हवाले से यह बताया गया है कि चार कारें नक़दी से भरी हुई थीं और उन्होंने सारा पैसा हेलिकाप्टर में भरने की कोशिश की, लेकिन सारी नक़दी हेलिकॉप्टर में नहीं भरी जा सकी और उन्हें कुछ धन वहीं रनवे पर ही छोड़ना पड़ा।' रूसी दूतावास की प्रवक्ता निकिता इशेंको के हवाले से रूसी वायर सेवा 'स्पूतनिक' ने यह खबर दी।❑❑

20 वर्ष बाद इतना मज़बूत कैसे हो गया तालिबान

वर्ष 2001 से शुरू हुई अमेरिका और मित्र सेनाओं की कार्रवाई में पहले तालिबान सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक धकेल दिया गया लेकिन 2012 में नाटो बेस पर हमले के बाद से फिर तालिबान का उभार शुरू हुआ। 2015 में तालिबान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कुंडूज के इलाक़े पर कब्ज़ा कर फिर से वापसी के संकेत दे दिए। ये ऐसा समय था जब अमेरिका में सेनाओं की वापसी की मांग ज़ोर पकड़ रही थी। अफग़ानिस्तान से अमेरिका की रुचि कम होती गई और तालिबान मज़बूत होता गया। इसी के साथ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की खुफिया मदद से पाक सीमा से सटे इलाकों में तालिबान ने अपना बेस मज़बूत किया। अफग़ानिस्तान से लौटने की अपनी कोशिशों के तहत 2020 में अमेरिका ने तालिबान से शांति वार्ता शुरू की और दोहा में कई राउंड की बातचीत भी हुई। एक ओर तालिबान ने सीधे वार्ता का रास्ता और दूसरी ओर बड़े शहरों और सैन्य बेस पर हमले की बजाय छोटे-छोटे इलाकों पर कब्ज़े की रणनीति पर काम करना शुरू किया। अप्रैल 2021 में अमेरिकी सेनाओं की वापसी के

बाक़ी पेज 11 पर

प्रवेश करते ही सीमाओं पर होगी सुखद अनुभूति

आने वाले समय में बाहर से आने पर दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचने पर अच्छा अनुभव महसूस कर सकेंगे। सीमाओं पर स्थित प्रवेश द्वारों को सुंदर बनाया जाएगा। राजधानी की ऐतिहासिक विरासत की झलक यहां दिखाई देगी। दिल्ली के सभी 12 प्रवेश द्वार सुंदर बनाए जाएंगे। इसमें से पहले चरण में पांच द्वारों का सुंदरीकरण किया जाएगा। इसमें टीकरीकलां द्वार (बार्डर) के लिए दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन (डीयूएसी) ने मंज़ूरी दे दी हैं मगर प्रवेश द्वार पर किसी तरह का निर्माण नहीं किया जाएगा। अब दिल्ली पर्यटन व परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) फाइनल मंज़ूरी के लिए दिल्ली सरकार के पास फाइल भेजेगा। टीकरीकलां बार्डन के सौंदर्यकरण पर करीब 12 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे।

डीटीटीडीसी टीकरी बार्डर के अलावा लोक निर्माण विभाग की ही सड़क पर आने वाले कापसहेड़ा और अप्सरा बार्डर के सौंदर्यकरण पर भी काम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। सभी प्रवेश द्वारों को 200 मीटर तक सुंदर बनाया जाना है। पहले और दूसरे चरण को मिलाकर दिल्ली के कुल 12 जगहों पर प्रवेश द्वारों को सुंदर बनाने का काम किया जाएगा। दिल्ली सरकार राजधानी के बड़े प्रवेश द्वारों के सुंदरीकरण की योजना पर काम कर रही है। इससे दिल्ली में प्रवेश करते ही सुखद अनुभूति होगी। प्रवेश द्वारों के 200 मीटर तक दिल्ली की विरासत और इसकी विशेषताओं को दर्शाया जाएगा।

दिल्ली सरकार ने वित्तवर्ष 2019-20 के बजट में दिल्ली के प्रवेश द्वारा को सुंदर बनाने के लिए योजना शामिल की थी। इसके लिए पहले चरण में गुरुग्राम बार्डर, टिकरी कलां बार्डर, गाजीपुर बार्डर, अप्सरा बार्डर और आनंद विहार बार्डर पर प्रवेश द्वारों को सुंदर बनाया जाना था। पहले चरण में पांच और दूसरे चरण में सात अन्य जगहों पर द्वारों को खूबसूरत बनाने का काम शुरू होना था। इन सभी प्रवेश द्वारों के सुंदरीकरण पर दिल्ली सरकार ने 25 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा था। लेकिन दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन द्वारा योजना में कुछ बिंदुओं पर एतराज़ जताने और कोरोना महामारी के चलते इस परियोजना में दूरी हो गई हैं। डीटीटीडीसी को पांच बार अपने मूल प्रस्ताव में बदलाव कर डीयूएसी को भेजना पड़ा, तब जाकर इसे मंज़ूरी मिल पाई है। डीयूएसी को एतराज़ प्रवेश द्वार पर स्थायी ढांचे के निर्माण को लेकर था, जिसका रास्ता निकाल लिया गया है। प्रवेश द्वार पर सुंदरीकरण को लेकर सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगें थे। अलग अलग तरह के सुझाए आए थे। एक सुझाव यह भी बताया जा सका कि दिल्ली किस तरह का शहर और भविष्य में कैसा बनेगा। लोगों ने सरकार को बहुत सारे सुझाव दिए।❑❑

आईआईटी दिल्ली व एम्स ने मिलकर विकसित किया टेलीरोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सैकड़ों किमी दूर बैठा कोई व्यक्ति आपका अल्ट्रासाउंड कर सकता है लेकिन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के वैज्ञानिकों ने इसे संभव कर दिखाया है। अब डॉक्टर किसी रिमोट लोकेशन से भी मरीज़ का अल्ट्रा साउंड कर सकेंगे। हाल ही में आई आईटी दिल्ली ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के साथ मिलकर एक टेलीरोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम विकसित किया है जिसकी एक रोबोटिक आर्म और इंटरनेट की मदद से डॉक्टर दूर लेटे मरीज़ का अल्ट्रासाउंड कर सकेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ख़र्च भी नहीं आएगा। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों को कोरोना महामारी के कारण आई परेशानियों के मद्देनज़र एम्स ने जून 2020 में दूर बैठकर अल्ट्रासाउंड करने की तकनीक की ज़रूरत बताई थी क्योंकि बीमारियों पर नकेल कसने के लिए अल्ट्रासाउंड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस पर अमल करते हुए आईआईटी दिल्ली व एम्स वैज्ञानिकों की एक टीम गठित की गई थी। इस रिसर्च को आईआईटी दिल्ली की ओर से प्रो0 चेतन अरोरा, प्रो. सुबीर कुमार साहा व एम्स की ओर से डॉ. चन्द्रशेखर और एडवर्ब टेक्नोलॉजी से सुबयन नंदी ने लीड किया। इनकी टीम में रिसर्च स्कॉलर दीपक रैना, डॉ. क्रिथिका रंगराजन, डॉ. आयुशी अग्रवाल व हर्षदीप सिंह भी शामिल रहे। कोरोना महामारी के दौर में यह तकनीक बहुत मददगार साबित होगी। इससे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी।

तकनीक के बारे में एम्स के डॉक्टर चन्द्रशेखर ने कहा कि अल्ट्रा सोनोग्राफ से दृश्य दिखेंगे एवं फिर वाई-फाई की सहायता से दृश्य डॉक्टर मॉनिटर पर ही ट्रांसमिट होंगे। डॉक्टर दृश्य देख मरीज़ के स्वास्थ्य का मूल्यांकन कर सकेंगे। आईआईटी दिल्ली के रिसर्च स्कॉलर दीपक रैना के मुताबिक आमतौर पर अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर (रेडियोलाजिस्ट) का मरीज़ के पास रहना आवश्यक होता है। कोरोना संक्रमण के चलते अल्ट्रासाउंड काफी प्रभावित हुआ है लेकिन टेलीरोबिटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम में डॉक्टर एक मॉनिटर की मदद से देश के किसी भी कोने में मरीज़ का आसानी से अल्ट्रासाउंड कर सकेगा। रोबोटिक आर्म डॉक्टर के इशारे पर अल्ट्रासाउंड करेगा और डॉक्टर मॉनिटर पर सभी दृश्य देख सकेंगे।❑❑

संपादकीय

शांति मिशन

जिंसी बेहयाई से समाज की हिफाज़त ज़रूरी

हाल में एक जाने/माने व्यवसायी और हिन्दी फिल्मों की एक अभिनेत्री के पति को पिछले दिनों मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का आरोप है कि यह व्यक्ति का अश्लील फिल्में बनाने का कारोबार कर रहा था और पूर्णबंदी के दौरान इसने सोशल मीडिया पर अश्लील फिल्मों को जारी कर करोड़ों रुपए कमाए। भारतीय दंड संहिता की धारा-292 के अनुसार अश्लील सामग्री की बिक्री और वितरण अवैध है। लेकिन यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि इंटरनेट पर ऐसी ढेर सारी सामग्री मौजूद है, जिस तक किसी भी स्मार्टफोन उपभोक्ता की पहुंच बड़ी आसान हैं। इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि सस्ते इंटरनेट प्लान ने जहां उपभोक्ताओं को सूचनाओं के विस्तृत तंत्र तक पहुंचने में मदद की है, वहीं एक बड़ी आबादी को सस्ती और अश्लील सामग्री की लत भी लगा दी। बेतरतीबी मानसिकता वाले लोगों ने सस्ते मोबाईल डेटा का उपयोग यौन कुंठाएं पैदा करने वाले वीडियो और फिल्में देखने में खुल कर किया। इस प्रवृत्ति ने उन लोगों की चांदी कर दी, जो लोगों की इस विकृत मानसिकता का लाभ अपना आर्थिक उल्लू सीधा करने में करते रहे हैं।

भारतीय परंपराओं में व्यक्ति के जीवन में यौन भावनाओं के अस्तित्व के महत्व को स्वीकार किया गया है। काम को धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ एक पुरुषार्थ का दर्जा दिया गया है लेकिन पुरुषार्थ कोई उच्छंखल क्रीड़ा नहीं होती, अपितु एक मर्यादा के साथ सम्पन्न किया गया सामाजिक दायित्व होता है। सामान्य तौर पर प्राचीन भारतीय समाज मनुष्य की यौन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के प्रति बहुत उदार था और समाज में इस अभिव्यक्ति को भी बहुत सर्जनात्मक तरीक़े से व्यक्त करने की परंपरा रही है। वात्स्यायन द्वारा रचा गया ग्रंथ कामसूत्र और कोणार्क, खजूराहों जैसे मंदिरों की बाहरी दीवारों पर बने चित्र इस बात का प्रमाण है लेकिनन भारतीय जीवन दर्शन का आग्रह यही था कि यह अभिव्यक्ति भी इस तरह से हो कि जीवन में कुंठा की बजाय सौंदर्यबोध जगाए। इस संबंध में एक रोचक मान्यता का उल्लेख किया जा सकता है। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कुछ मंदिरों को 'भंडदेवरा' कहा जाता है। भंड शब्द की उत्पत्ति लोकभाषा के बंड शब्द से हुई है जिसे शरारती व्यक्ति के लिए विश्लेषण के तौर पर प्रयोग किया जाता है।

ये बात दुखदायी ही कही जाएगी कि अश्लील फिल्मों के संदर्भ में इस तरह की सुरक्षा सरकारें भी नहीं कर सकीं। ऐसे प्रकरण भी सामने आए हैं जब किसी बलात्कार के बाद अपराधियों ने क़बूला कि उन्होंने अपराध की साज़िश अपने फोन पर अश्लील फिल्म देखने के बाद रची। 80 के दशक की बात है। उन दिनों तो इंटरनेट तक बहुत कम लोगों की पहुंच हो पाई थी। लेकिन वीडियो कैसेट के माध्यम से अश्लील फिल्में दिखाने का धंधा पैर पसारने लगा था। राजस्थान के आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले में एक छोटा होटल वाला लोगों से पैसे लेकर एक कमरे में अश्लील फिल्में दिखाने का धंधा करता था। उसके ग्राहकों में ज़्यादातर मजहूर और आदिवासी हुआ करते थे। मामला तब खुला जब एक दिन कुछ महिलाओं ने उस दुकान के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का कहना था कि उनके पति न केवल अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अश्लील फिल्में देखने में ख़त्म कर देते हैं, बल्कि घर लौटने पर अपनी पत्नियों से अपेक्षा करते हैं कि वे वैसे ही सब करें जैसी फिल्म में कथित नायिका ने की थी। वैसा नहीं करने पर पुरुष मारपीट करते थे। यह वही दौर था जब जम्मू कश्मीर में एक सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता का अश्लील वीडियो सामने आने की ख़बर मीडिया में सुर्ख़ियों में रही थी। जब वीडियो कैसेट को वीडियो प्लेयर पर देखा जाता था, तब तो फिर भी अश्लीलता के नाखून किसी बंद कमरे या कैबिन तक सीमित रहा करते थे, लेकिन स्मार्टफोन ने तो अश्लीलता को मानो हर कहीं विचरने का लाइसेंस दे दिया है। देश के कुछ विधान सदनों में तो माननीय विधायक तक सत्र के दौरान अपने मोबाईल की स्क्रीन पर अश्लील फिल्में देखते हुए पाए गए। मीडिया में भी उनकी चर्चा भी खूब हुई। लेकिन ऐसी हरकतें करने वाले माननीयों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई, यह ख़बर कभी पढ़ने में नहीं मिली। जबकि लोकतंत्र में ऐसे नेताओं के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई आम आदमी को भी कुछ संदेश दे सकती थी।

जिंसी कारोबार को काफी पुराना है क्योंकि यह सभ्य समाज में भी आदिम मर्यादाओं को पोषित करता है। दुनियाभर में इन दिनों गंदी फिल्मों का कारोबार फल-फूल रहा है। अनेक देशों में गंदी सामग्री का निर्माण और वितरण प्रतिबंधित है। लेकिन इंटरनेट पर ऐसी लाखों साइटें हैं जो किसी न किसी रूप में उपभोक्ता तक प्रतिबंधित सामग्री पहुंचा ही देती है। पश्चिमी जीवन की उन्मुक्तता ने तो अश्लीलता को एक बड़े बाज़ार में तब्दील कर दिया है। वर्ष 2008 में यह अनुमान लगाया गया था कि उस वर्ष दुनिया में कामुकता बढ़ाने वाली सामग्री की बिक्री तीस लाख डॉलर तक पहुंच जाएगी और उसी वर्ष विजनगेन नामक एक पत्रिका का कहना था कि तीन वर्ष में ही अमेरिका में अश्लील फिल्मों का व्यापार सात करोड़ डॉलर के आंकड़े को छू लेगा। यह 15 वर्ष पुरानी बात हैं तब से अब तक दुनिया की नदियों में होकर बहुत सा पानी समुद्र में पहुंच गया है। फ्री मोबाईल डेटा और इंटरनेट ने हर आदमी के लिए अश्लील साइटों तक पहुंचना सबसे आसान कर दिया है हालांकि देश की सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर भारत सरकार ने आठ सौ से अधिक अश्लील साइटों को बैन किया है, लेकिन इंटरनेट पर तो उनकी संख्या लाखों में है। ये साइटें कई तरह से लोगों के जीवन को बर्बाद करती हैं। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि अमेरिका में बलात्कार के दोषी पाए गए 53 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट पर पहले अश्लील फ़िल्में देखी थी अश्लील सामग्री ने बच्चों के प्रति अपराध बढ़ाए हैं।

जिन लोगों की ख़ासी सामाजिक प्रतिष्ठा है, जिन्हें दुनिया उनकी सकारात्मक या सर्जनात्मक उपलब्धियों के लिए जानती है, वे भी धनार्जन के लालच में नीली फिल्मों के काले कारोबार से जुड़े दिखें तो संवेदनशील लोग चौंकते हैं। हालांकि सब जानते हैं कि धन का लालच व्यक्ति को कई बार अविवेकी बना देता है। पिछले दिनों मुंबई में पकड़े गए नामचीन व्यापारी के अश्लील फिल्मों के निर्माण के प्रकरण में जांच एजेंसियां और क़ानून तो अपना-अपना काम करेंगे ही, लेकिन यह चुनौती तो समाज को ही स्वीकार करनी होगी कि वह ऐसी सामग्री के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरुक करे। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अश्लील फिल्में न केवल मनुष्य का पारिवारिक जीवन तहस नहस कर देती है, बल्कि उसे ऐसे मनोरोगों का भी शिकार बना देती है कि जीवन आनंद की अनुभूति से कोसों दूर हो जाता है।

बहरहाल यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह समाज को इस गंदगी से बचाने के लिए कोई सार्थक क़दम उठाए और पहले से मौजूद क़ानूनों पर अमल कराने को सुनिश्चित करें। जिन्सी आवारगी और अश्लीलता की जिस बीमारी पर हमने अपने संपादकीय कॉलम में प्रकाश डाला है, वह अपने बच्चों को बचाने हेतू है, जिससे वाल्दैन अपने बच्चों पर नज़र रखें, इसलिए हमें विशेष तौर स्वयं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस्लाम हमें एक ऐसे निज़ामे हयात का पाबंद बनाता है जो कुरआन करीम और अहादिसे मुबारका की तालीम के ज़रिए मुरत्तब होता है, इस्लाम और उसके निज़ाम को अल्लाह ने पूरा पेश कर दिया है अब अगर मुसलमान अपने आपको इस्लाम के दिए हुए निज़ामें ज़िन्दगी के अनुसार बिताना चाहता है तो उसके लिए उस पर अमल करना ज़रूरी है इसलिए हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिय कि हमारे बच्चे ग़ैर इस्लामी तरीक़े अपनाकर अश्लीलता और आवारगी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं और अगर ऐसा है तो हमारी पहली ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को फैशन, अश्लील फिल्मों और स्मार्टफोन की हया और शर्म समाप्त करने वाले कामों से बचाने के लिए ठोस रणनीति बनाएं और उस पर सख़्ती से अमल करें, यहां हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि एक ऐसे समय में जबकि बच्चों के बिगाड़ने के लिए हर स्तर पर अलग-अलग तरह के प्रोग्राम तैयार हो रहे हैं, हम अपने बच्चों को घरों में दोस्ताना माहौल बनाकर अच्छे अंदाज़ में उनकी तर्बियत करते हुए उन्हें समझाएं कि हमारे पास इस्लाम के रूप में अल्लाह का दिया हुआ एक ऐसा बेहतरीन निज़ाम है जिसके अनुसार ज़िन्दगी गुज़ारने से दुनिया भी बनती है और आख़िरत भी। इस रणनीति के अनुसार अगर हम यह काम करने में सफल हो गए तो उससे न केवल हमारे बच्चों को एक भरपूर इस्लामी ज़िन्दगी का मार्ग मिलेगा बल्कि उस पर चलना भी उनकी ज़िन्दगी का मक़सद बन जाएगा।

हमें याद रखना चाहिए कि वर्तमान स्थिति में बच्चों को बिगड़ने, जिंसी आवारगी और बेहयाई को फैलाने वाली सामग्री का ढेर लगा हुआ है अगर वाल्दैन शुरू से ही अपने बच्चों को इस्लामी तर्बियत करें और उन्हें दीनी शिक्षा से संवारते रहे तो हमारे यह बच्चे इस्लामी ज़िन्दगी का नमूना बनकर सामन आएंगे जो जहां उनके भविष्य के लिए बेहतर होगर वही वह मां-बाप के लिए भी आख़िरत के लिए भी ज़ख़ीरा साहबत होगा। ❑❑

तारीख़े इस्लाम

ख़ुतबाते सीरते तैयिबा

मुफ़्ती मुहम्मद सलमान मंसूरपुरी क़िस्त- 86

सुलहे हुदैबिया

ग़ज़वा-ए-ओहुद और ग़ज़वा-ए-ख़न्दक़ के बादख मुशरिकीन-ए-मक्का पर एक रोब और हैबत तारी हो गई, इसी दरमियान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक ख़्वाब देखा कि आप सहाबा-ए-किराम रज़ि अल्लाहु अ़न्हुम के साथ उमरा के लिए तशरीफ़ ले गए, और उमरा के बाद कुछ लोगों ने सर के बाल पूरी तरह मुंडवाये हैं, और कुछ लोगों ने कतरवाये हैं, नबी का ख़्वाब भी बरहक़ और वही के दर्जे में होता है, अगरचे इस ख़्वाब में यह तय नहीं किया गया था कि आप को कब जाना है लेकिन आप ने ज़िल कअ़दा सन 6 हि0 में इस ख़्वाब को अ़मली शकल देने का इरादा फ़रमा लिया, और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ 1400 सहाबा उमरा का ऐहराम बाँध कर मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। ज़ाहिर है कि उमरा में लड़ाई का कोई तसव्वुर और ख़्याल भी नहीं था, और मक्का मुअ़ज़्ज़मा से आए हुए 6 साल गुज़र चुके थे, बैतुल्लाह शरीफ़ की ज़ियारत करने और उमरा से मुशर्रफ़ होने की लोगों के दिलों में तमन्ना भी थी, आ़म तौर पर तमाम क़बाइल के लोग उमरा के लिए साल भर आते जाते थे, क्योंकि बैतुल्लाह शरीफ़ पर तो किसी की भी इजारा दारी नहीं है, कोई भी किसी भी वक़्त जाये और उमरा कर के आए, इस लिए नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने निज़ाम बना लिया और चौदह सौ सहाबा के साथ आप तशरीफ़ ले चले। अल-रौज़ुल अनफ़ जि. 4, स. 40)

जब मक्का वालों को आप की तशरीफ़ आवरी की ख़बर मिली तो वहाँ पर एक तरह का हंगामा सा हो गया, और उन्होंने अपनी बेइ़ज़्ज़ती समझी कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सहाबा के साथ यहाँ तशरीफ़ लायें और बख़ैरियत वापस चले जायें। (जारी)

कांग्रेस देवभूमि को बदनाम करे और हम उनकी सच्चाई भी न बताए, यह संभव नहीं

दुष्यंत कुमार गौतम

उत्तराखंड में सियासी गर्मी रोज़-ब-रोज़ बढ़ती ता रही है। अगले छह महीनों में वहां विध ानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले भाजपा को पिछले चार माह में दो मुख्यमंत्री बदलने पड़े हैं लेकिन उसने नारा दिया है - इस बार 60 पार, भाजपा बार-बार। उधर, कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में अपनी हार देखकर भाजपा धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण पर अमादा है, इसके लिए वह राज्य के सद्भाव को नष्ट कर रही है। दो-दो मुख्यमंत्री बदलने से पड़ने वाले असर से लेकर धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोपों तक ऐसे तमाम मसलों पर भाजपा क्या कहती है, यह जानने के लिए उत्तराखंड के भाजपा प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम से हुई एक विशेष बातचीत के अंश यहां पेश किए जा रहे हैं।

प्रश्नः- इस बार 60 पार, भाजपा बार-बार, इस नारे पर आप लोग ख़ुद कितना यक़ीन कर पा रहे हैं?

उत्तरः- अगर यक़ीन नहीं होता, तो हम लोग यह नारा देते ही क्यों? 2014 के बाद नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के राजनीतिक परिदृश्य में जो बदलाव आय, उसके बाद राज्यों में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, एक दो अपवाद छोड़कर ज़्यादातर में भाजपा ही ने जीत दर्ज की है। इनमें वे राज्य भी शामिल हैं, जहां भाजपा ने पहली बार सत्ता में वापसी की। उत्तराखंड में भी हम 2002 में पहले से कहीं ज़्यादा बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं।

प्रश्नः- राज्य में अगर सब कुछ भाजपा के हक़ में ही है तो केन्द्रीय नेतृत्व को वहां दो-दो मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े?

उत्तरः- यह ग़लतफहमी है कि वहां कुछ गड़बड़ थी, इसलिए दो बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े। यह भाजपा है, यहां मुख्यमंत्री कौन है, यह बात

जहां तक एंटी इन्कबेंसी फैक्टर की बात है, वह उत्तराखंड में है ही नहीं। अगर जनता के बीच सरकार को लेकर ज़रा भी नाराज़गी होती तो विपक्ष सड़कों पर होता। लेकिन राज्य में सरकार के ख़िलाफ़ विपक्ष तक ख़ामोश है, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। रही बात उत्तराखंड के मिजाज़ की है, तो इतिहास सिर्फ दोहराया ही नहीं जाता, बल्कि बनाया भी जाता है। हमने बनाया भी है।

मायने नहीं रखती, मायने रखती है भाजपा की नीतियां। मुख्यमंत्री कोई भी हो, उसे भाजपा की नीतियों के अनुरूप सरकार चलानी होती है। जनता ने हमारी नीतियों पर वोट किया है। भाजपा में यह भी नहीं होता कि कोई मुख्यमंत्री बन गया तो परमानेंट मुख्यमंत्री हो गया। नेतृत्व ज़रूरत देखकर समय-समय पर सबकी भूमिका बदलता रहता है।

प्रश्नः- भाजपा उत्तराखंड में 2022 का चुनाव पुष्कर सिंह धामी के ही नेतृत्व में लड़ेगी, या सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा?

उत्तरः- धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं हम उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे।

प्रश्नः- एंटी इंकम्बेंसी फेक्टर भी बहुत मायने रखता है और उत्तराखंड का मिजाज़ हर पांच वर्ष पर सरकार बदलने का है?

उत्तरः- जहां तक एंटी इन्कबेंसी फैक्टर की बात है, वह उत्तराखंड में है ही नहीं। अगर जनता के बीच सरकार को लेकर ज़रा भी नाराज़गी होती तो विपक्ष सड़कों पर होता। लेकिन राज्य में सरकार के ख़िलाफ़ विपक्ष तक ख़ामोश है, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। रही बात उत्तराखंड के मिजाज़ की है, तो इतिहास सिर्फ दोहराया ही नहीं जाता, बल्कि बनाया भी जाता है। हमने बनाया भी है। उत्तखंड में भी हम बनाने जारहे हैं - लगातार दूसरी जीत करने का।

प्रश्नः- लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा अपने हाथ से बाज़ी निकलते देख धार्मिक ध्रुवीकरण का हथियार इस्तेमाल कर राज्य के सद्भाव को नष्ट कर रही है..?

उत्तरः- राज्य के सद्भाव को भाजपा नहीं, कांग्रेस नष्ट कर रही है। सिर्फ सद्भाव को ही नष्ट नहीं कर रही है, बल्कि वह देवभूमि को बदनाम भी कर रही है। पूरी दुनिया में कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया कि कोरोना हरिद्वार के कुंभ की वजह से फैला। केरल में किसकी वजह से फैला, इस पर अपनी ज़ुबान नहीं खोली? क्यों नहीं खोली? क्योंकि उसके ज़रिए वह धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण चाहती है और इल्ज़ाम हम पर लगाया जा रहा है। कांग्रेस देवभूमि को बदनाम करे और हम उनकी सच्चाई भी न बताएं, यह संभव नहीं है।

प्रश्नः- राज्य में भाजपा के बहुत सारे पॉवर सेंटर हैं, बहुत सारे सीएम के दावेदार भी हैं इसका कुछ असर पड़ेगा या नहीं?

उत्तरः- राज्य में केवल एक पॉवर सेंटर है, वह है भाजपा। भाजपा अपनी नीतियों और अपने नेतृत्व को आगे कर वोट मांगती है, उत्तराखंड में भी मांगेगी, कहीं कोई गुटबाज़ी है ही नहीं।

पूरी दुनिया में कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया कि कोरोना हरिद्वार के कुंभ की वजह से फैला। केरल में किसकी वजह से फैला, इस पर अपनी ज़ुबान नहीं खोली? क्यों नहीं खोली? क्योंकि उसके ज़रिए वह धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण चाहती है और इल्ज़ाम हम पर लगाया जा रहा है। कांग्रेस देवभूमि को बदनाम करे और हम उनकी सच्चाई भी न बताएं, यह संभव नहीं है।

प्रश्नः- आम आदमी पार्टी भी वहां चुनाव लड़ने जा रही है, वहां के राजनीतिक समीकरणों में कितना बदलाव हो सकता है?

उत्तरः- जो पार्टी दिल्ली में फेल हो चुकी है, उसके उत्तराखंड में कामयाबी के कोई चांस ही नहीं है। राज्य में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार भी नहीं है, बस मीडिया के ज़रिए ख़बरों को वह प्लांट कराती रहती है।

प्रश्नः- तो भाजपा की सीधी लड़ाई कांग्रेस के साथ है.?

उत्तरः- वहां हमारी किसी से कोई लड़ाई ही नहीं हे। हमने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे, उससे कहीं ज़्यादा काम करके दिखाया। कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा इलाक़ा नहीं, जिसके लिए पांच वर्षों में काम न हुआ हो। हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे और अगले पांच साल उनकी सहमति प्राप्त करेंगे।

प्रश्नः- राज्य की जनता से भाजपा का वादा क्यों होगा?

उत्तरः- समृद्ध राज्य बनाएंगे, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के भरपूर अवसर उपलब्ध होंगे। ❑❑

भले ही मेरा पैर टूट जाता, मेडल तो चाहिए था : बजरंग पूनिया

तोक्यो ओलिंपिक में पहलवान बजरंग पूनिया ने अपने पैर में तकलीफ होने के बावजूद मेडल जीता। कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित बजरंग पूनिया ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर इतनी बड़ी सफलता पाई है। पेश बजरंग पूनिया से ओलिपिंक पदक जीतने के बाद हुई एक बातचीत के प्रमुख अंश :-

प्रश्नः- अब आगे की योजना क्या है?

उत्तरः- मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार मैं अपने देशवासियों की अपेक्षा पूरी नहीं कर पाया। लेकिन 2024 में जो पेरिस में ओलिंपिक होने वाला है, उसके लिए मैं अभी से ही मेहनत करूंगा और देश को निराश नहीं करूंगा।

प्रश्नः- फाइनल मुक़ाबले में आने से पहले किस तरह के संघर्षों से गुज़रना पड़ता है?

उत्तरः- यह सच है, कि सेमीफाइनल में हारने के बाद मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, लेकिन जब मेरे कोच बृजभूषण जी ने बहुत ही प्यार से कहा कि जो हो गया उसे भूल जाओ। जो सामने है उसे देखो और उसी पर अपना फोकस रखो। तुम्हें तकलीफ है, इसमें कोई संशय नहीं है फिर भी तुम्हें पदक जीतना ही हैं फिर मैंने फाइट की और रिजल्ट आपके सामने है।

प्रश्नः- दाहिना घुटना चोटिल होना ही तो कहीं कांस्य पदक तक सीमित रहने की वजह नहीं है?

उत्तरः- डॉक्टर ने तीन-चार सप्ताह आराम को कहा था, लेकिन मैंने नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि एक पैर पर अधिक भार देने से बाएं पैर की भी मसल्स खिंच गई। इसके कारण मेरा मूवमेंट सही तरीक़े से नहीं हो पा रहा था। तब मेरे फिजियोथेरेपिस्ट मनीष जी ने कहा कि यह समय भी निकल जाएगा। अगर मूवमेंट सही से होता, तो आज मेडल का रंग कुछ और ही होता।

प्रश्नः- आपने डॉक्टरों की सलाह नहीं मानी, तो क्या आगे 65 किलोग्राम वजन वर्ग बदलने की कोई संभावना है?

उत्तरः- ओलिपिंक में मेडल जीतना ही मेरा सपना था। यह सपना साकार हुआ। इसकी मुझे बेहद ख़ुशी है और इसके लिए ईश्वर को ध न्यवाद देता हूं। मेरे लिए पैर से अधिक पदक जीतना ज़्यादा ज़रूरी था। भविष्य में वजन वर्ग बदलने की कोई संभावना नहीं हैं मेरा वेट 65 किलोग्राम ही रहेगा।

प्रश्नः- चोट की वजह से आप 25 दिनों तक प्रशिक्षण से दूर रहे। उस बीच ख़ुद को कैसे मोटिवेट करते थे.?

उत्तरः- उस समय आराम के साथ-साथ दिन में दो या तीन बार एक्सरसाइज करने के लिए भी कहा गया था। फिर भी मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं एक्सरसाइज इससे अधिक कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। इसमें कोई दिक्क़त नहीं है। दरअसल मैं दिन में सोता नहीं था इसलिए मुझे जितना समय मिलता था, पैर की एक्सरसाइज करता था। इसके सिवाय मेरे पास कोई काम नहीं था।

प्रश्नः- क्या पहले से ही माइंड सेट रहता है कि पदक तो जीतना ही है?

उत्तरः- सच पूछो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस तरह किसी भी फील्ड में बेहतरीन करने के लिए जी-तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही खेल में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मेहनत करने से ही हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं। मैंने भी अपने खेल को बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत की थी।

प्रश्नः- तोक्यो ओलिपिंक की तैयारियों में विदेशी कोच की कितनी भूमिका रही है?

उत्तरः- मेरे विदेशी कोच की भूमिका बहुत रही है, इससे मैं इंकार नहीं कर सकता। उनका नाम शाकू है और वह जार्जिया के रहने वाले है। हालांकि वह मेरे पर्सनल कोच हैं। इसके अलावा जगबिंदरजी और अनिल मानजी का भी हमारे ऊपर बहुत फोकस रहता है। अगर मुझ से कोई ग़लती होती थी, तो दोनों आपस में बातचीत करते थे। उन्होंने हम पर बहुत मेहनत की है। दोनों का मुझे बहुत सहयोग मिला है।

प्रश्नः- सेमीफाइनल में हारने के बाद भी आपको जीत की उम्मीद थी?

उत्तरः- जिस तरह हमारे जीवन में हार-जीत चलती रहती है, वैसे ही खेल में भी चलती है। जो बीत गई, सो बात गई। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता हूं। अब जो सामने बचा हुआ है, उसी पर फोकस करना है। उस समय दिमाग़ में बस एक ही बात चलती रहती थी कि हर हाल में मुझे अब जीतना है। चाहे पैर ही क्यों न टूट जाए, पर मेडल तो चाहिए ही। ❑❑

देश को चाहिए मुफ़्तख़ोरी से आज़ादी

आज हम अपने स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाने में व्यस्त हैं। पर अभी तक हमारे देश में कई तरह की बुराईयां व्याप्त हैं इनमें से एक मुफ्तख़ोरी भी है। तमाम देशों में इस समय जनता को मुफ़्त सुविधाएँ बांटकर वोट हासिल करने का सिलसिला ज़ोर पकड़ रहा है। इंग्लैंड के पिछले चुनाव में मुफ़्त ब्राडबैंड, बस यत्रा एवं कार पार्किंग की घोषणा की गई। हम भी पीछे नहीं। कुछ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में मुफ्त लेपटाप, तमिलनाडू के हालिया चुनावों में किचन ग्राउंडर एवं साइकिल, दिल्ली में मुफ्त बिजली एवं पानी और केन्द्र सरकार द्वारा गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इनसे जनहित तो होता है, मगर कहावत है कि किसी को 'मछली बांटने के स्थान पर यदि उसे मछली पकड़ना सिखाएं तो वह अधिक लाभप्रद होता है।' विचारणीय है कि ऐसे मुफ्त वितरण से क्या वास्तव में जनहित होता है? चुनाव पूर्व ऐसी घोषणाएं निश्चित रूप से अनैतिक हैं, क्योंकि इनमें सार्वजनिक धन का उपयोग वोट मांगने के लिए किया जाता है। जैसा कि कांग्रेस ने किसानों की ऋण माफी एवं मनरेगा जैसी योजनाओं से जीत हासिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पूर्व ऐसी बंदरबांट पर रोक लगाने की पहल की थी।

बड़ा प्रश्न यही है कि क्या चुनाव के बाद भी ऐसा वितरण सही है? भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद की प्रोफेसर रितिका खेड़ा के अनुसार सरकारी सेवाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली श्रेणी में सार्वजनिक सेवाएं होती है। जैसे रेल, हाईवे अथवा कोविड के बारे में जानकारी जो कि केवल सरकार ही उपलब्ध करा सकती है। नि:संदेह ये सुविधाएं सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दूसरे प्रकार की सुविधाएं वे होती हैं जो व्यक्ति स्वयं हासिल कर सकता है, परंतु किसी व्यक्ति को ये सुविधाएं मिलने से समाज का भी हित होता है। जैसे यदि किसी को मास्क मुफ्त दे दिया जाए तो कोविड संक्रमण कम होगा। यद्यपि मास्क व्यक्तिगत सुविधा है, परंतु उसे उत्तम अथवा मेरिट वाली सुविधा कहा जाता है। तीसरे प्रकार की सुविधाओं में लाभ व्यक्ति विशेष को ही होता है। जैसे दिल्ली में एक तय सीमा तक मुफ्त बिजली देना। ऐसे वितरण का सामाजिक सुप्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सरकार को इससे बचना चाहिए। उसे सीधे देने के स्थान पर जनता को सक्षम बनाना चाहिए कि वह इस सुविधा को स्वयं बाज़ार से खरीद सके।

विषय यह रह जाता है कि मैरिट और व्यक्तिगत सुविधा में भेद कैसे किया जाए? इसका स्पष्टीकरण दो योजनाओं की तुलना से हो सकता है। केन्द्र सरकार ने किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देने की योजना लागू की है। वहीं दिल्ली सरकार ने मुफ़्त बिजली और पानी देने का वादा किया है। दोनों मुफ्त सुविधाएं हैं। अंतर है कि किसान को नक़द राशि मिलने से उसका खेती के प्रति रुझान बढ़ता है और देश की खाद्य व्यवस्था सुदृढ़ होती है, जबकि बिजली मुफ्त बांटने से ऐसा लाभ नहीं मिलता। इसलिए किसान को दी जाने वाली नक़द मदद को मेरिट सुविधा में गिना जाना चाहिए जबकि मुफ़्त बिजली को व्यक्तिगत सुविधा में। इसका यह अर्थ नहीं कि किसान को नक़द राशि देना ही सर्वोत्तम है। उत्तम यह होता कि किसान को पराली न जलाने, भूजल के पुनर्भरण, रासायनिक उर्वरक का उपयोग घटाने के लिए सब्सिडी दी जाती। इससे किसान की आय भी बढ़ती और समाज का हित भी होता। केन्द्र सरकार को तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए। वर्तमान में केन्द्र द्वारा किसान पेंशन के अतिरिक्त मातृत्व वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं को नक़द राशि दी जा रही है। उन्नत जीवन योजना के अंतर्गत एलईडी बल्ब वितरित किए जा रहे हैं। ग्रामीण कौशल योजना एवं दीनदयाल अंत्योदय कौशल योजना के अंतर्गत लोगों को उपयुक्त क्षमताओं में प्रशिक्षण दी जा रही है। इन योजनाओं को बनए रखना चाहिए, लेकिन केन्द्र द्वारा तमाम मुफ्त सुविधाएं भी दी जा रही हैं। जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत बीमा पर सब्सिडी दी जा रही है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जा रही है। जन-धन योजना में बैंक में खाते खुलवाए जा रहे हैं। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत ग़रीबों को लगभग मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। इन तमाम योजनाओं का विशेष सामाजिक सुप्रभाव नहीं दिखता। उलटे प्रशासनिक भ्रष्टाचार से रिसाव का जोखिम और पैदा होता है। इन योजनाओं की रक़म को लोगों के खाते में सीधे वितरित कर दिया जाए तो बेहतर। इससे न केवल इन योजनाओं में प्रशासनिक व्यय और भ्रष्टाचार की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी, अपितु लाभार्थी तक वास्तविक लाभ भी पहुंचेगा। दूसरा लाभ यह होगा कि जनता अपने विवेक एवं आवश्यकतानुसार उस रक़म का उपयोग कर सकेगी।

आज देश के नागरिक जागरुक हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जाता है कि वे अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में शिक्षा दिलाने के लिए ख़र्च करने से गुरेज़ नहीं करते। अब उस धारणा को तिलांजलि दे देनी चाहिए कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति केवल सरकारी तंत्र ही कर सकता है। हमें जनता पर भरोसा कर उसे इन तमाम योजनाओं में उलझाने के बजाए सीधे रकम देनी चाहिए।

आज हमारे देश के नागरिक जागरुक हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जाता है कि वे अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में शिक्षा दिलाने के लिए ख़र्च करने से गुरेज़ नहीं करते। अब उस धारणा को तिलांजलि दे देनी चाहिए कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति केवल सरकारी तंत्र ही कर सकता है। हमें जनता पर भरोसा कर उसे इन तमाम योजनाओं में उलझाने के बजाए सीध रकम देनी चाहिए। ऐसे वितरण के विरोध में कहा जाता है कि यदि देश के सभी नागरिकों को यह रक़म दी जाएगी तो यह अमीरों को भी मिलेगी, जिसका कोई तुक नहीं। मान लीजिए किसी अमीर को किसान की भांति 6,000 रुपये सालाना नक़द दिए गए तो वे उससे अतिरिक्त कर के रूप में वसूल भी किए जा सकते हैं। इससे लाभ यह होगा कि ग़रीब पर 'ग़रीब' का ठप्पा नहीं लगेगा और नौकरशाही के खेल से देश मुक्त हो जाएगा।

कल्याणकारी ख़र्चों का दूसरा पक्ष सरकार की वित्तीय क्षमता का है। सरकार को निर्णय करना होता है कि वह सड़क बनाएगी अथवा ग़रीब को पेंशन देगी। सरकार जब जनता को मुफ्त सुविधाएं देती हैं तो उसकी हाईवे इत्यादि बनाने की क्षमता कम हो जाती है। वह नई तकनीक में निवेश नहीं कर पाती। इसका आख़िरकार देश के आर्थिक विकास पर ही कुप्रभाव पड़ता है। परिणामस्वरूप ग़रीब का ही जीवन दुष्कार हो जाता है। वेनेजुएला इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तमाम सुविधाएं मुफ्त प्रदान करने से आज उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। समय आ गया है कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने के लिए मुफ्तखोरी पर विराम लगाना चाहिए इसके बजाय नई तकनीकों में निवेश किया जाए और नागरिकों को सीधे रक़म दी जाए। ❑❑

रोज़गार .....

एक आकर्षक रिज्यूमे कैसे बनाएं

एक अच्छा रिज्यूमे आपकी नौकरी की 50 प्रतिशत गारंटी होता है। अगर रिज्यूमे आपके शैक्षणिक और व्यक्तिगत गुणों से भरपूर और संतुलित है तो आपको नौकरी के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। गूगल को बीते वर्ष 2019 में किसी भी अन्य वर्ष की तुलना में अधिक आवेदन प्राप्त हुए-लगभग 3.3 मिलियन (33 लाख) दिलचस्प बात यह है कि टैक दिग्गज रिज्यूम को स्क्रीन करने के लिए 'बॉट' का उपयोग नहीं करते। एक वास्तविक व्यक्ति हर रिज्यूमे को पढ़ता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ''गूगल में, हम अभी भी काम पर रखने के लिए मनुष्यों पर निर्भर हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण काम है। हम लोगों को कौशल और योग्यता के लिए रिज्यूमे देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। उम्मीदवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कागज का वह टुकड़ा आपके सभी आयामों को ठीक से कैसे दर्शा सकता है।''

गूगल जैसी कंपनियां अपनी एच. आर. टीम को ऐसे लोगों को तलाशने के लिए प्रशिक्षित करता हैं, जो दूसरों से हटकर हों, इन चार चीज़ों को आप अपने रिज्यूमे में शामिल कर सकते हैं।

1. आपका अनुभव

अपने रिज्यूम को अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के अवसर के तौर पर देखें। विशेषज्ञों के मानना है कि ''हम लोगों को न केवल यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि उन्होंने यहां काम किया या स्कूल गए, बल्कि उनके द्वारा प्राप्त अनुभव और उनके द्वारा सीखे गए पाठों को व्यक्त करने के लिए भी।''

वह कहती है, यदि आपने हाल ही में स्नातक की है तो अकादमिक शोध, शिक्षण अनुभव और हालिया छात्र समूह या कक्षा परियोजनाओं जैसे अनुभव शामिल करें। इसके अलावा, पेशेवर उपलब्धियों का प्रदर्शन करें और साथ ही काम और जीवन के प्रतिच्छेदन (इंटरसैक्शन) को उजागर करें।

2. आपके परिणाम और प्रभाव

आपने जो सीखा है, उसके अलावा, अपनी पिछली भूमिकाओं और परियोजनाओं में आपके द्वारा छोड़े प्रभाव के बारे में सोचें। लोगों को अक्सर रिज्यूमे में डाटा का उपयोग करना सिखाया जाता है, लेकिन इसे प्रभाव से जोड़ा जाना चाहिए। डाटा का वर्णन करने के लिए वाक्यों को शामिल करें। आपको इसे एक साथ लाने के लिए भाषा की आवश्यकता है।

यदि आप एक व्यावसायिक भूमिका के लिए आवेदन कर रहे हैं, उदाहरण के लिए खाता प्रबंधन में तो आपने जो हासिल किया है, उसे कैसे मापा गया और कैसे किया गया, इसे सांझा करके अपने अनुभव को व्यक्त करें। उदाहरण के लिए-''मैंने अपने ग्राहकों के व्यावसायिक लक्ष्यों के समाधान के तौर पर नई सॉफ्टवेयर सुविधाओं का मानचित्रण करके 15 छोटे ग्राहकों से राजस्व में तिमाही-दर तिमाही 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।''

3. जब आप अपना अनुभव और परिणाम साझा करते हैं, रोशनी डालने हेतु विशेषताओं की पहचान करने के लिए नौकरी विवरण पर एक गाइड के रूप में विचार करें। इन कीवडर्स पर पूरा ध्यान दें क्योंकि वे अक्सर वही होते हैं जिन्हें भर्तीकर्ता विशिष्ट भूमिकाओं को भरने के लिए रिज्यूमे पर देखते हैं। इसका एक शॉर्टकट है किसी भी महत्वपूर्ण शब्द पर सक्रिय रूप से रोशनी डालना, जो आपके मौजूदा कौशल और ज्ञान के साथ संरेखित है और आपके रिज्यूमे में क्या प्रासंगिक है, इसमें शामिल है।''

4. आप किसी संगठन में क्या योगदान डाल सकते हैं

उम्मीदवार यह बताए कि वह संगठन में क्या लाता है, केवल वह नहीं जो उसे उस भूमिका के उपयुक्त बनाता है। ''चूंकि आपका रिज्यूमे अक्सर भर्ती करने वालों के लिए आपकी पहली छाप होता है, भूमिका और अपनी वरिष्ठता के आधार पर, शीर्ष पर एक संक्षिप्त सारांश अनुभाग जोड़ने पर विचार करें। प्रासंगिक कार्य अनुभव और आप संगठन में क्या योगदान डाल सकते हैं, इन पर ध्यान दें।''

आप हाल की नौकरी की भूमिकाओं की सूचि के बजाय पिछले अनुभव के गुणात्मक और मात्रात्मक उदाहरण प्रदान करके भी रिज्यूमे का महत्व बढ़ा सकते हैं। ''गूगल में, हम हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो हमें मज़बूत टीम, उत्पाद और सेवाएं बनाने में मदद करने के लिए नए दृष्टिकोण और जीवन के अनुभव लाते हैं।'' आप अपना रिज्यूमे बनाएं तो अपने व्यक्ति गुणों के साथ, अपनी हॉबिस, आस/पास का स्वच्छ वातावरण का भी वर्णन करते हैं। ❑❑

इस्लामी दुनिया

लेबनान में टैंकर में विस्फोट, 20 मरे

बेरुत : उत्तरी लेबनान में ईंधन के एक टैंकर में विस्फोट होने से 20 लोगों की मौत हो गई तथा कई अन्य लोग घायल हो गए। विस्फोट की वजह साफ नहीं है। लेबनान के रेड क्रॉस की ओर से बताया गया कि 'तलेइल गांव से उसके दलों को 20 शव मिले हैं। विस्फोट में घायल हुए और झुलसे लगभग 80 लोगों को निकाल लिया गया है।

पाकिस्तान में ट्रक पर हमला, 11 की मौत

कराची : पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची में पिछले दिनों हमलावरों ने एक ट्रक को निशाना बनाकर हथगोला फेंका, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि ट्रक पर महिलाओं और बच्चे समेत करीब 20 लोग सवार थे और वे शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। हमला कराची के बाल्डिया शहर में हुआ।

शरणार्थियों की नाव पलटी 24 लोगों के डूबने की आशंका

ढाका : बंगाल की खाड़ी में एक नाव पलटने से उसमें सवार दो दर्जन से ज़्यादा रोहिंग्या शरणार्थी लापता हो गए और उनके डूब जाने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र और बांग्लादेश की पुलिस ने यह जानकारी दी। नाव में सवार शरणार्थी एक बांग्लादेश द्वीप से भागने का प्रयास कर रहे थे। म्यांमार की सीमा के पास शिविरों में रहने के बाद इस द्वीप पर कई हज़ार रोहिंग्या को स्थानांतरित किया गया था।

मलेशियाई प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा

मलेशियाई प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासिन ने सत्ता संभालने के 18 माह से भी कम समय में मलेशिया के नरेश को इस्तीफा सौंप दिया। वह देश की सत्ता में सबसे कम समय तक आसीन रहे नेता बन गए हैं। वह मार्च 2020 में प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले उन्होंने यह स्वीकार किया था कि शासन करने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन उन्हें हासिल नहीं है। विज्ञान मंत्री खैरी जमालुद्दीन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मंत्रिमंडल ने नरेश को इस्तीफा सौंप दिया है। यासिन मलेशिया नरेश से मिलने राजमहल पहुंचे। उन्होंने इस्तीफा दिया। उप खेल मंत्री वान अहमद फयहसल वान अहमद कमाल ने फेसबुक पर पोस्ट लिखी, जिसमें मुहिउद्दीन के नेतृत्व और सेवा के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया।

ऑनलाइन शिक्षा और चुनौतियाँ

सुधीर कुमार

महामारी ने देश में तकनीक आधारित शिक्षा की सही तस्वीर सामने रख दी। बुनियादी संरचना के अभाव, बिजली की किल्लत और महंगे और इंटरनेट की समस्या के कारण ऑनलाइन शिक्षा को मुकम्मल ऊंचाई नसीब नहीं हो पा रही है। हाल में आई एकीकृत ज़िला शिक्षा सूचना प्रणाली की 2019-20 की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के पन्द्रह लाख स्कूलों में से केवल 38.54 प्रतिशत स्कूलों में ही कंप्यूटर उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश के महज़ 13.59, मेघालय के 13.63, पश्चिम बंगाल के 13,87, बिहार के 14.19 और असम के पन्द्रह प्रतिशत स्कूलों में ही कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है।

महामारी के दौर में भारत मे प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा की उपयोगिता को नया आयाम मिला है। देश की शिक्षा व्यवस्था इस वक्त यथाशक्ति ऑनलाइन व्यवस्था में ढलती जा रही है। देशभर के शैक्षणिक संस्थान सवा साल तक बंद ही रहे। हालांकि अब राज्यों ने शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने की दिशा में क़दम बढ़ाए हैं। लेकिन अब ऑनलाइन शिक्षण एक व्यापक विकल्प के तौर पर स्थापित हो गया हैं पर यह भी सच्चाई है कि महामारी ने स्कूल प्रबंधकों, कोचिंग संचालकों, अस्थायी शिक्षकों और कर्मचारियों की अर्थव्यवस्था और जीवन को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। साथ ही, करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य भी अभी अधर में ही है। भविष्य की चिंता के कारण वे हताशा और अवसाद के शिकार हो रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों के लंबे समय तक बंद रहने के कारण विद्यार्थियों का सर्वांगिण विकास भी प्रभावित हुआ है। स्कूल परिसर का वातावरण छात्रों में दायित्व बोध का भाव भरता है। स्कूल महज़ चंद कमरों की संरचना नहीं होती, बल्कि वहां बच्चे शिक्षा के साथ संस्कार और जीवन का पाठ भी सीखते हैं। स्कूल परिसर में सहपाठियों के साथ सामाजिकता का विकास होता हैं। बच्चों में एक सुसंस्कृत और ज़िम्मेदार नागरिक की नींव पड़ती है। ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, जो ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में लागू नहीं होती हैं।

लेकिन ऑनलाइन शिक्षा माध्यम का जो एक और पक्ष भी सामने आया है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। तथ्य यह है कि देश के स्कूलों में प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस मामले में हमारे स्कूल अभी भी बहुत पीछे हैं। महामारी ने देश में तकनीक आधारित शिक्षा की सही तस्वीर सामने रख दी। बुनियादी संरचना के अभाव, बिजली की किल्लत और महंगे और इंटरनेट की समस्या के कारण ऑनलाइन शिक्षा को मुकम्मल ऊंचाई नसीब नहीं हो पा रही है। हाल में आई एकीकृत ज़िला शिक्षा सूचना प्रणाली की 2019-20 की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के पन्द्रह लाख स्कूलों में से केवल 38.54 प्रतिशत स्कूलों में ही कंप्यूटर उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश के महज़ 13.59, मेघालय के 13.63, पश्चिम बंगाल के 13,87, बिहार के 14.19 और असम के पन्द्रह प्रतिशत स्कूलों में ही कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। अगर बात करें स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है। केरल और दिल्ली के स्कूलों में क्रमशः अठासी और छियासी प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन दूसरी ओर त्रिपुरा में महज़, 3.85 प्रतिशत, मेघालय में 3.88 और असम में 5.82 फीसदी स्कूलों में ही इंटरनेट कनेक्शन है। ज़ाहिर है, तकनीकी शिक्षा और संचार के आधुनिकतम तकनीक से हमारे विद्यार्थी आज भी कोसों दूर हैं। तकनीकी युग में कम्प्यूटर और इंटरनेट की गिनती मूलभूत सुविधाओं में होती है। ऑनलाइन शिक्षा के दौर में सरकारी स्कूलों के पिछड़ने की यह एक मुख्य वजह है, जिस पर नीति नियंताओं को सोचने की आवश्यकता है।

महामारी के कारण दुनियाभर में स्कूली शिक्षा बाधित हुई है। संक्रमण से बचाव की कोशिशों के तहत दुनिया के एक सौ नब्बे से अधिक देशों को अपने स्कूलों के दरवाज़े बंद करने पड़े। यूनेस्को के मुताबिक कोविड-19 की शुरुआत के बाद दुनिया के एक सौ अड़तालीस देशों के गरीब डेढ़ अरब छात्रों की शिक्षा स्कूलों के बंद होने से बाधित हुई है। स्कूली शिक्षा में आए इस व्यवधान के बाद एक विकल्प के रूप में ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन तेजी से तो बढ़ा है, लेकिन इस तरह की शिक्षा की पहुंच हरेक तक नहीं हो पाई। इकोनॉमिस्ट इंटेलीजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट बताती है कि स्कूलों के बंद रहने से दुनियाभर में एक अरब साठ करोड़ स्कूली बच्चों में से केवल दस करोड़ स्कूली बच्चों की ही शिक्षा बाधित होने से बच पाई। यानि ऐसे बच्चे स्कूल बंद होने के बावजूद घर पर रहकर आगे की पढ़ाई कर पाने में सक्षम हो पाए हैं। इसका एकमात्र बड़ा कारण घर पर तकनीक की सुलभता की रहा। लेकिन दूसरी ओर ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच से दूर करोड़ों बच्चों का भविष्य अधर में है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो ग्रामीण इलाकों में या छोटे शहरों में तो स्मार्टफोन की अनुपलब्धता, बाधित विद्युत व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने में असमर्थता और धीमे इंटरनेट जैसी समस्याओं ने बच्चों के भविश्य पर ग्रहण लगा दिया है। सरकारें भले ही देश में सौ प्रतिशत विद्युतिकीरण का सपना पूरा होने की बात कह कर अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन देश में विद्युतीकरण और विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2017-18 में कराया गया एक सर्वे बताता है कि देश में सोलह फीसद परिवारों को प्रतिदिन एक से आठ घंटे, तैंतीस प्रतिशत परिवारों को नौ से बारह घंटे और सिर्फ सैंतालीस प्रतिशत परिवारों को ही बारह घंटे से अधिक बिजली मिलती है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए बिजली के साथ-साथ स्मार्टफोन या कम्प्यूटर और इंटरनेट की सुविधा का उपलब्ध होना प्रमुख शर्त है लेकिन इस मामले में हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 2017-18 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण रिपोर्ट की मानें तो देश के केवल चौबीस प्रतिशत परिवारों के पास ही इंटरनेट की सुविधा है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा कैसे समूचे देश के बच्चों को निर्बाध रूप से उपलब्ध होगी, यह बड़ा प्रश्न है।

दरअसल, हक़ीक़त यह है कि देश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे निम्न आय वर्ग के परिवारों से आते हैं। उनके पास न तो स्मार्टफोन की सुविधा होती है और न ही इंटरनेट पैक खरीदने की हैसियत। ऐसे परिवारों में ग़रीबी, जागरुकता और तकनीकी ज्ञान के अभाव में प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा की आवश्यकता को पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया जाता है। ऐसे में देश के करोड़ों बच्चे चाह कर भी ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते। ग्रामीण क्षेत्रों के वे बच्चे जिनके पास संसाधनों का घोर अभाव है, ऑनलाइन शिक्षा के दौर में निश्चय ही पिछड़ जाएंगे। लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई का क्रम टूटा है। ऐसे में पढ़ाई के प्रति मोह कम होना भी स्वाभाविक ही हैं जब स्कूल दोबारा खुलेंगे तो ज़ाहिर है कि बच्चों के लिए पढ़ाई में पुनः उसी प्रकार से जुटना आसान नहीं होगा। लाखों बच्चे तब तक स्कूल भी छोड़ चुके होंगे। महामारी ने बच्चों को स्कूल से जोड़ने की सारी क़वायदों को भारी धक्का पहुंचाया है।

ऑनलाइन शिक्षा समाज में एक गहरा विभेद भी उत्पन्न कर सकती हैं। कुछ समय पहले यूनेस्को ने भारत को सचेत करते हुए कहा था कि शिक्षा पाने के लिए यह सोचना गलत है कि ऑनलाइन सीखना हर किसी के लिए आगे का रास्ता खोलता है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई से दूर-दराज़ के इलाक़ों में रह रहे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए किसी विशेष वर्ग की दी जाने वाली शिक्षा सामाजिक विभेद को बढ़ाएगी। ऐसे में सरकार को इन बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए, जो स्कूल से दूर होकर अपने भविष्य को दांव पर लगाने को विवश हैं। (2020-21) के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि अगर ऑनलाइन शिक्षा का सही इस्तेमाल किया जाता है तो इससे शैक्षणिक परिणाम में होने वाली असमानताएं ख़त्म होंगी लेकिन क्या ऑनलाइन शिक्षा की सर्व-सुलभता के बिना इस असमानता को ख़त्म कर पाना मुमकिन होगा? ❑❑

ऑनलाइन पढ़ाई से दूर-दराज़ के इलाक़ों में रह रहे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए किसी विशेष वर्ग की दी जाने वाली शिक्षा सामाजिक विभेद को बढ़ाएगी। ऐसे में सरकार को इन बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए, जो स्कूल से दूर होकर अपने भविष्य को दांव पर लगाने को विवश हैं। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि अगर ऑनलाइन शिक्षा का सही इस्तेमाल किया जाता है तो इससे शैक्षणिक परिणाम में होने वाली असमानताएं ख़त्म होंगी लेकिन क्या ऑनलाइन शिक्षा की सर्व-सुलभता के बिना इस असमानता को ख़त्म कर पाना मुमकिन होगा?

अजय शुक्ल

अवसरवाद का पर्याय बन गई है राजनीति

महात्मा गांधी का मानना था, कि लक्ष्य की सफलता तब है, जब उसके लिए पवित्र साधन और रास्ते अपनायें जायें। राज्य व्यवस्था में लोकतंत्र को श्रेष्ठ माना गया है। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे पहले आई। इसका प्रमाण ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है, जहां राजा अपनी सभा और मंत्रिपरिषद् के विमर्श के बाद ही कोई नीति, नियम और निर्णय करता था। गणतंत्र शब्द भी सबसे पहले ऋग्वेद में 40 बार, अथर्ववेद में नौ बार और ब्राह्मण ग्रंथों में कई बार प्रयोग किया गया। देवराज इन्द्र कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पद था, जो चुना जाता था।

वैदिक काल में ग्राम शासन भी देखने को मिलता है। हड़प्पा की सभ्यता के मिले अवशेषों से भी पता चलता है कि वहां के नगरीय शासन को चलाने के लिए नगर निगम जैसी लोक सभायें होती थीं, जो जनहित को ध्यान में रखकर फैसले लेती थीं। वैदिक काल के बाद राजतंत्र का अस्तित्व सामने आता है, जहां से बुराईयां भी पैदा होती हैं। 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहरकर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जिस लोकतंत्र की शुरुआत की थी, उसके बूते हम आज खुद को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दम भरते हैं। आज़ादी के डेढ़ दशक बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था बदलने लगी, जो अवसरवादिता को बढ़ाने वाली थी। 21वीं सदी की शुरुआत के साथ यह पूरी तरह से अवसरवादी हो गई। सत्ता पर काबिज़ होने के लिए अब साधनों और रास्तों की पवित्रता नहीं देखी जाती है।

आपको आज़ादी के पहले की कुछ घटनायें याद दिलाना ज़रूरी है। ब्रिटिश काल में जार्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को पहले गोल मेज सम्मेलन की शुरुआत की थी। सम्मेलन में 13 प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार के और 76 भारतीय रिसायतों, राजनीतिक दलों, अल्पसंख्यकों तथा दलितों के थे। कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। इसमें डॉ. भीमाराव अंबेडकर ने जातिवाद और कट्टरपंथी हिन्दुओं को जमकर लताड़ा था। उन्होंने कहा था कि ''मैं जिन अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में यहां आया हूं, उनकी संख्या हिन्दुस्तान की कुल जनसंख्या का पांचवां भाग है, जो ब्रिटेन और फ्रांस की जनसंख्या के बराबर है। उनकी दशा गुलामों से भी बदतर है। वे जातिवादी और कट्टरपंथी हिन्दुत्व व्यवस्था में घृणित और पशुवत जीवन-यापन कर रहे हैं। उन्हें छूना पाप माना जाता है वे मंदिर नहीं जा सकते हैं और न ही कुओं से पानी ले सकते हैं।

उन्हें कोई अधिकार भी नहीं है। हालांकि यह भी सत्य है कि डॉ. अंबेडकर को इस योग्य बनाने में एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर की भूमिका थी। उन्होंने ही अपना उपनाम डॉ. अंबेडकर को दिया था। उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर भी ब्राह्मण थीं।

उन्होंने अपने के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। बड़ोदरा रियासत के महाराज सयाजी गायकवाड़ ने न सिर्फ डॉ. अंबेडकर को विदेश में पढ़ाया बल्कि नौकरी भी दी थी। अवसरवादी राजनीतिक के चलते उन दोनों के नाम का ज़िक्र कभी कहीं किया भी नहीं जाता। 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस 85 प्रतिशत भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

डॉ. अंबेडकर ने इसमें दलितों को हिन्दुओं से अलग अल्पसंख्यक का दर्जा दे, स्थायी आरक्षण की मांग की थी, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। गांधी जी ने सांप्रदायिकता को बड़ी समस्या बताया। मुस्लिम और सिखों के साथ प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडॉनाल्ड ने मध्यस्थता की, मगर सफल नहीं रहे। गांधी जी ने पूर्ण स्वराज के कांग्रेस फैसले से ब्रिटिश हुकूमत को अवगत कराया। गोलमेज का दूसरा सम्मेलन अवसरवादी सांप्रदायिक राजनीति के कारण असफल रहा था। भारत के लोगों को बांटने की राजनीति का आरोप लगाकर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारत के प्रमुख नेताओं दलों ने हिस्सा नहीं लिया था। पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, सभी अवसरवादी राजनीति का शिकार हुए थे। कई दल और नेता उस समय अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतवासियों की मांग का विरोध कर रहे थे।

ऐसे नेताओं के कारण ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। अंग्रेज़ों का साथ देने का ईनाम मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना और विनायक दामोदर सावरकर की हिन्दू महासभा को मिला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगुआई में हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर तीन राज्यों में सरकार बनाई। जहां ये दोनों सरकार चला रहे थे, वहीं भारत विभाजन के समय सबसे अधिक सांप्रदायिक हिंसा भी हुई। यह अवसरवादी राजनीति का एक वीभत्स चेहरा था। हालांकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन्ना यूरोपियन शैली में रहते थे। उनके यहां अधिकतर हिन्दू कर्मचारी थे। वह कट्टरवाद के समर्थक नहीं थे, मगर जब सत्ता संघर्ष शुरू हुआ तो उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथी का चेहरा दिखाकर देश को बांटने का काम किया। जिन्ना की पत्नी पारसी थीं, तो उनकी बेटी दीना जिन्ना ने भी पारसी भारतीय नेविले वाडिया से शादी की।

जिन्ना की दूसरी पत्नी भी ग़ैर मुस्लिम थी। बावजूद इसके, जिन्ना कट्टर मुस्लिम चेहरा बने, जिससे वह पाकिस्तान के पहले वज़ीरे-ए- आज़म बन सके। मौजूदा राजनीति में भी हम यही अवसरवादिता देख रहे हैं। हम चंद विकास योजनाओं के एक मॉडल पर चर्चा कर समझें। 2006 से 2012 तक केन्द्र शासित चंडीगढ़ में विकास योजनाओं पर चर्चा होती थी। यहां मैट्रो, मेडीसिटी, एक्यूजमेंट पार्क, आईटी सिटी और एजूकेशन पर काम हो रहा था। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित तमाम राज्यों में विकास के मॉडल और योजनाएं आ रही थीं। देश के तमाम औद्योगिक घराने अपने प्रोजेक्ट्स लगाने में जुटे थे। करोड़ों युवाओं के रोज़गार की व्यवस्था हो रही थी। अचानक देश के हालात बदले और 2012 के बाद एक नई राजनीतिक बहस शुरू हुई।

जिन्ना की दूसरी पत्नी भी ग़ैर मुस्लिम थी। बावजूद इसके, जिन्ना कट्टर मुस्लिम चेहरा बने, जिससे वह पाकिस्तान के पहले वज़ीरे-ए-आज़म बन सके। मौजूदा राजनीति में भी हम यही अवसरवादिता देख रहे हैं। हम चंद विकास योजनाओं के एक मॉडल पर चर्चा कर समझें। 2006 से 2012 तक केन्द्र शासित चंडीगढ़ में विकास योजनाओं पर चर्चा होती थी। यहां मैट्रो, मेडीसिटी, एक्यूजमेंट पार्क, आईटी सिटी और एजूकेशन पर काम हो रहा था। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित तमाम राज्यों में विकास के मॉडल और योजनाएं आ रही थीं। देश के तमाम औद्योगिक घराने अपने प्रोजेक्ट्स लगाने में जुटे थे। करोड़ों युवाओं के रोज़गार की व्यवस्था हो रही थी। अचानक देश के हालात बदले और 2012 के बाद एक नई राजनीतिक बहस शुरू हुई। तमाम परियोजनाएं आरोपों में घिरकर रद्द हो गई। कई क़ानूनी पचड़ों में फंस गईं।

अब चंडीगढ़ में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं रहा। इसी तरह तमाम अन्य राज्यों में भी हुआ। इस वक्त देश में 40 करोड़ से अधिक बेरोज़गारों की फौज तैयार हो चुकी है। मनरेगा योजना सबसे बड़ा रोज़गार दाता बन गई हैं। देश में 80 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त अनाज वाली योजना की लाइन में लगने को मजबूर हैं। सांप्रदायिक, कट्टरपंथी और जातिवादी नीति के पोषक, अवसरवादी नेताओं दलों ने एक ऐसी हमजोली बनाई है कि उनके नेता एक दूसरे को गाली देकर अपना बड़ा वोट बैंक तैयार करते हैं। यह वोट बैंक कट्टर अंध भक्तों का होता है। कोई जाति के नाम पर, तो कोई धर्म के नाम पर एकजुट होता है।

जो राष्ट्र को विकास के बजाय विनाश की राह ले जाता है। इसका लाभ अवसरवादी राजनीति करने वाले चंद नेताओं और दलों को होता है। वे इसके नाम पर धन भी इकट्ठा करते हैं और सभी सुख भी भोगते हैं। अंधभक्ति में उनको वोट देने वाले नफ़रत की लड़ाई में मरते हैं। हमें उस वैदिक और हड़प्पा की सभ्यता वाले लोकतंत्र को स्थापित करना चाहिए, जहां सर्वजन हिताए, सर्वजन सुखाय की सोच होती थी। हमें विचारशील बनना पड़ेगा क्योंकि हम विश्व बंधुत्व की संस्कृति वाले राष्ट्र हैं।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सही ही कहा है कि इस देश के मुस्लिमों का भी वही डीएनए है, जो यहां के हिन्दुओं का हैं जाति धर्म की कट्टरता में ही हमारा देश पहले भी कई बार टूटा है और अब फिर उसी नफ़रत की आग में जल रहा है। हमें उसे बचाना है। इसके लिए देश के नागरिकों को पहल करनी होगी। हमें सर्वजन विकास को लेकर चर्चा करनी चाहिए, न कि जाति धर्म के विघटन की। अगर हमने समय रहते अवसरवादी राजनीति और राजनीतिज्ञों को किनारे नहीं लगाया, तो भविष्य हमारा और हमारे बच्चों को बर्बाद होना तय है। हम इस राजनीति के दो पटों में पिसकर अपना जीवन खत्म कर लेंगे। ❑❑

ख़ास ख़बरें

अमेरिका में स्पोर्टस बार के बाहर गोलीबारी

सैन एंटोनिया : अमेरिका के सैन एंटोनियो में एक स्पोर्ट्स बार के बाहर एक व्यक्ति ने गोलियां चलाकर तीन लोगों की हत्या कर दी। इसमें दो अन्य घायल हो गए। सेन एंटोनियो के पुलिस प्रमुख विलियम मैकमैनुस ने बताया कि बार के बाहर गोली की यह घटना तड़के तीन बजे हुई। एक व्यक्ति कार के पास गया और बड़ी सी बंदूक लेकर लौटा। उसने पार्किंग स्थल पर पांच लोगों को गोली मार दी।

इला गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के लिए मदद मांगी

जोहानिसबर्ग : महात्मा गांधी की पोती इला गांधी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में हाल में हुई हिंसा के बाद भारत को देश के पुनर्निर्माण के प्रयासों में उसकी मदद करनी चाहिए। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित एक आयोजन में भारतीय वाणिज्य दूतावास से एक प्रतिनिधि के रूप में गांधी ने कहा कि डरबन के उत्तर में विशाल भारतीय बस्ती, फीनिक्स में हाल ही में हुई हिंसा, जिसने निवासियों और तीन पड़ोसी अनौपचारिक बसावटों के काले लोगों के बीच तनाव पैदा किया, उसके लिए आपराधिक मंशा वाले लोग ज़िम्मेदार थे जिनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

ब्रिटेन के आतंकी समूह से जुड़े दो सदस्य गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने दो कथित आतंकवादियों को गिरफ्तार किया हैं इनके पास से दो ग्रेनेड और दो पिस्तौल बरामद किए है। यह जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिनकर गुप्ता के मुताबिक, अमृतसर से ब्रिटेन स्थित आतंकवादी संगठन से जुड़े दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी ब्रिटैन में रहने वाले आतंकवादी गुरप्रीत सिंह खालसा उर्फ गुरप्रीत के निर्देश पर काम कर रहे थे। उन्हें सीमा पार से भेजे गए हथियारों की खेल लाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी।

अमेरिका भारत में संबंध बढ़ रहे : संधू

अमेरिका के साथ भारत के संबंध निरंतर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों को इन संबंधों से आधिकारिक लाभ प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में और अधिक सहयोग करने की आवश्यकता है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने यह बात कही।

सहाबा कराम और उनके औसाफ़

किस्त-1

जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत की तकमील के लिए हज़रत मौहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का चयन फरमाया और आप (सल्ल॰) की ज़ात को इस के लिए हर तरह से तैयार किया फिर आप पर तब्लीग़ रिसालत का भार डाला और कुरआन करीम नाज़िल करके इंसानी दुनिया को इसकी शिक्षाओं से रोशनास कराने की तल्क़ीन की। इसी तरह आप (सल्ल॰) के लिए जो साथी चयनित किए कए वह अपने आप में बड़ी महत्ता के पात्र थे इनकी ज़िन्दिगयां आप (सल्ल॰) की आदम, बईश्त और आप (सल्ल॰) पर ईमान लाने से पहले अजीब व ग़रीब विरोधाभासों का शिकार थीं, वह अमल के कोरे फिक्र व नज़र से खाली, अख़्लाकियात से आरी, बेहंगम ज़िन्दगी गुज़ारने के आदी, शराबे नाब के रसिया और हर तरह की बुराइयों के दिल दादाह थे। मगर जूं ही नबी पाक (सल्ल॰) की निगाहें रहमत इनकी ओर केन्द्रित हुई इनके ज़ाहिर व बातिन की काया पलट कर रह गयी। फिर इनकी ज़िन्दगियों में ऐसा इंक़लाब आया कि इसकी मिसाल इस दुनिया ने न तो पूर्व के लम्बे मानवीय इतिहास में कभी देखी थी और न भविष्य के दिनों में ऐसा हो पाया, वह दौर जिसमें नबी पाक (सल्ल॰) अपने असहाब के साथ इस दुनिया में मौजूद रहे, जो कुल 23 वर्ष के समय, पर आधारित है वह इंसानी इतिहास का अफज़लतरीन, बेहतरीन हैरतअंगेज़, इंक़लाबों का केन्द्र, हक़ की सरबुलंदी और बातिल की पराजय व आत्मसमर्पण का ऐसा नमूना था जिसे हर कोई देख और महसूस कर सकता था।

आप (सल्ल॰) को सहाबा की जो जमाअत मिली थी वह आप (सल्ल॰) ही की तरह चयनित थी अल्लाह ने ख़ासतौर से आपकी मुसाहबत के लिए ही उन्हें पैदा किया था, इस्लाम लाने के पहले वह बुराईयों की पोट थे मगर दामने इस्लाम से जुड़ाव के बाद वह ऐसे बदले कि खुद अच्छाईयां इन पर रश्क़ करने लगीं, शराफ़त को इनसे दवाम मिला, हक़ परस्ती को आबरू नसीब हुई, सदक़ व सफा के मोती इन्हीं के ज़रिए चमके, अख़्लास व वफा को वक़ार व ऐतबार मिला। सहाबा की सीरत आदत, बल्कि इनकी पूरी ज़िन्दगी में जो तब्दीली हुई, इसमें एक तो खुद इलाही मसलहत का दख़ल था कि अल्लाह-तबारक तआला ऐसा ही चाहते थे चुनाँचे ऐसा ही हुआ मगर इसके साथ-साथ एक और बात यह भी थी कि इन लोगों को रसूले (सल्ल॰) खुदा जैसी मरबी, कामिल, बेलौश मोहसिन शफीक़ उस्ताद मिला। लिसान अल अस्र, अकबर इलाहाबादी ने नबी पाक (सल्ल॰) की पुर तासीर नज़र और सहाबा कराम की ज़िन्दगी में आने वाले हैरतअंगेज़ इन्क़लाब की तरफ इशारा करते हुए खूब कहा है :-

खुदा न थे जो राह पर औरों
के हादी बन गए
क्या नज़र थी जिसने मर्दों को
मसीहा कर दिया!

कुरआन करीम में जगह-जगह सहाबा ए रसूल के औसाफ़ बयान किए गए हैं। राहे हक़ में इनकी कुर्बानियों का ज़िक्र किया गया है, इनके मरतबे आलिया की वज़ाहतें की गयीं हैं और दुनिया ही में इन्हें रज़ा-ए-इलाही की खुश खबरियों से नवाज़ा गया है। सूरह अलफतह की एक लम्बी आयत है जिसमें सहाबा कराम की अमली विशेषताओं का ज़िक्र है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ''मौहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग इनके साथ हैं वह कुफ़्फ़ार पर सख़्त और आपस में रहम दिल हैं तुम उन्हें रुकू और सज्दे में मशगूल पाओगे, वह अल्लाह के फज़ल और उसकी रज़ा की तलब में लगे रहते हैं। इनकी निशानियां

यूं तो इनकी यही विशेषता सबसे बड़ी थी कि उन्होंने अल्लाह के महबूब नबी (सल्ल॰) को देखा इनकी जनाब में बारयाबी का शर्फ हासिल किया था मगर इनके साथ मिलकर इलाह हक़ के रास्ते में उन्होंने जिस जाँ सुपारी के साथ क़ुर्बानियां पेश कीं इसने उन्हें अल्लाह के नबी (सल्ल॰) की निगाह में और अल्लाह तबारक व तआला के यहां भी बड़ा सर बुलंदियों का पात्र बना दिया।

(शनाख़्त नामे) इनकी पेशानियों पर हैं सज्दों की वजह से। यही इनकी सिफ्त तौरयत में भी बयान की गयी) है और इन्जील में इनकी मिसाल यूँ दी गयी है कि गोया एक खेती है जिसने पहले कोंपल निकाली, फिर उसको तकवीयत दी, फिर इसमें और मज़बूती आयी, फिर वह अपने तने पर खड़ी हो गयी ताकि कुफ़्फ़ार इनके फलने-फूलने पर जलें। इनमें से जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया इनके लिए अल्लाह ने मग़फरत और अज्र अज़ीम का वादा किया है।''

सहाबा कराम की ज़िन्दगियों की नक्शाकशी इससे ज़्यादा जामेअ अंदाज़ में नही हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी हर खसूसियत को इस आयत में खोल कर रख दिया है, यूं तो इनकी यही विशेषता सबसे बड़ी थी कि उन्होंने अल्लाह के महबूब नबी (सल्ल॰) को देखा इनकी जनाब में बारयाबी का शर्फ हासिल किया था मगर इनके साथ मिलकर इलाह हक़ के रास्ते में उन्होंने जिस जाँ सुपारी के साथ क़ुर्बानियां पेश कीं इसने उन्हें अल्लाह के नबी (सल्ल॰) की निगाह में और अल्लाह तबारक व तआला के यहां भी बड़ा सर बुलंदियों का पात्र बना दिया, इनमें से हर एक के दिल में अपने नबी (सल्ल॰) अल्लाह तबारक व तआला और अपने दीने-मतीन की ऐसी मोहब्बत जाग गयी थीं कि वह इस राह में अपना सब कुछ कुर्बान करने को हर वक़्त तैयार रहते थे। यही वजह है कि आप (सल्ल॰) ने भी विभिन्न मौक़ों पर अपने सहाबा की अज़मत को बयान फरमाया और उम्मत को तलक़ीन की कि वह न सिर्फ इनकी ताज़ीम व तकरीम को अपना दीनी व ईमानी फरीज़ा समझे बल्कि इनकी ज़िन्दगी और सीरत व किरदार को अपनाते हुए ज़िन्दगी भी गुज़ारें। आपने एक अवसर पर इर्शाद फरमाया 'मेरे सहाबा को गालियां न देना, उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान हैं अगर तुम में से कोई व्यक्ति ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे। (अल्लाह के रास्ते में) तो इनमें से किसी एक के खर्च किए हुए मद (मामूली मिक़दार) के बराबर भी नहीं पहुंच सकता (सही-मुस्लिम, किताब अल फज़ाइल)।

इस हदीस पाक से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस्लाम में सहाबा कराम की अज़मत कितनी अधिक है और अल्लाह के रास्ते में इनकी दी गयी कुर्बानियों की क़द्र व क़ीमत किस क़दर आला है। इसी तरह एक और हदीस में जो बहुत ही मशहूर हैं और जुमे में खुत्बे के दौरान इमाम साहब उसे पढ़ते हैं, आप (सल्ल॰) ने क़यामत तक के लिए पूरी उम्मत को सावधान करते हुए फरमाया ''मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, जिसने इनसे मोहब्बत की, इसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे बुग़ज़ रखा इसने मुझसे बुग्ज़ रखा और बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के लोग हैं फिर जो उनके बाद आने वाले हैं।'' इस हदीस से भी सहाबा कराम की बेपनाह अज़मत का इज़हार होता है कि नबी पाक (सल्ल॰) इन से मोहब्बत को अपनी मोहब्बत की अलामत क़रार दे रहे हैं और इनसे बुग्ज़ को अपनी ज़ात से बुगज़ की अलामत क़रार दे रहे हैं।

सहाबा कराम की अज़मत और गौरव का तक़ाज़ा था कि इस्लाम नबी पाक (सल्ल॰) के बाद भी व्यक्तिगत तथा सामूहिक तौर पर इनकी जमाअत को मुसलमानों के लिए नमूना-ए-अमल और आइडियल क़रार देता, सो इसने जहां यह कहा कि ''नबी की ज़ात तुम्हारे लिए असवाए हसना और बेहतरीन नमूना अमल है।' वहीं नबी पाक (सल्ल॰) की जुबानी यह भी कहलवाया गया कि ''तुम मेरी और मेरे खुल्फाए राशिदीन की इत्तबा करना'' और यह कि ''मेरे सहाबा हिदायत से जिसकी भी इत्तबा करोगे, राहेयाब हो जाओगे। (जारी)

नूरे क़ुरआन

(सूरा वज्जुहा नं॰ 93)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

यह सूरा मक्का में उतरी इसमें 11 आयतें हैं।

प्रारंभ करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।

कसम है धूप चढ़ते समय की और रात की जब वह छा जाये कि आपके पालनहार ने आपको छोड़ा और न आप से दुश्मनी की।

हदीसों में है कि जिब्रील अलै॰ देर तक मुहम्मद सल्ल॰ के पास न आये (अर्थात् कुरआन का वह्यी बन्द रही) मुशरीकीन (अल्लाह का साझी बनाने वाले) कहने लगे कि मुहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया। उसके जवाब में यह आतें उतरीं। मौलाना उसमानी का विचार यह है कि यह थोड़े दिनों वह्यी के रुक जाने का वह समय है। जब सूरा इक़रा की प्रारंभिक आयतें उतरने के पश्चात् एक लम्बे समय तक वह्यी रुकी रही थी और हुज़ूर सल्ल॰ इस वह्यी के रुकने के समय में बड़े शोकाकुल और ग़मग़ीन रहा करते थे। यहां तक कि फरिश्ते ने अल्लाह की ओर से (ऐ, कपड़े में लिपटने वाले) इसकी तफ़सीर (व्याख्या) सूरा नं॰ 73 में आ चुकी है, कहकर संबोधित किया। हो सकता है उस समय विरोधियों ने इस प्रकार की बातें कहीं हों, चुनांचे इब्ने क़सीर ने मुहम्मद बिन इस्हाक़ आदि से जो शब्द लिखे हैं, वह इसी संभावना का समर्थन करते हैं। संभवत: इसी बीच यह क़िस्सा भी सामने आया हो, जो कुछ हदीसों में वर्णन किया गया है कि एक बार हुज़ूर सल्ल॰ बीमारी के कारण तीन रात न उठ सके, तो एक इंकारी औरत कहने लगी कि ऐ हज़रत मुहम्मद सल्ल॰ ज्ञात होता है कि तेरे शैतान ने तुझको छोड़ दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन समस्त बकवासों का उत्तर इस सूरा वज्जुहा में दिया गया हैं। पहले क़सम खाई धूप चढ़ते वक़्त की और अंधेरी रात की, फिर कहा (दुश्मनों के तमाम विचार ग़लत हैं) न तेरा रब तुझसे नाराज़ और और न तुझको छोड़ा, बल्कि जिस प्रकार प्रत्यक्ष में वह अपनी शक्ति, तात्विकता की भिन्न-भिन्न निशानियां दिखाता है और दिन के पश्चात् रात, रात के पीछे दिन लाता है, यही दशा मनुष्य के आंतरिक हालात की समझो। अगर सूरज की धूप के पश्चात् रात के अंधेरे का आना अल्लाह की प्रसन्नता और नाराज़ी का प्रमाण नहीं और न इसका सबूत है कि इसके पश्चात् दिन का उजाला कभी न होगा, तो कुछ दिन वह्यी के प्रकाश के रुके रहने से यह कैसे समझ लिया जाये कि आजकल अल्लाह अपने चुने हुए रसूल से अप्रसन्न और नाराज़ हो गया और सदैव के लिए वह्यी का दरवाज़ा बंद कर दिया। ऐसा कहना अल्लाह के असीम ज्ञान और पूर्ण तात्विकता पर लांछन लगाना है। अर्थात् जैसे उसको ख़बर न थी, जिसको मैं रसूल बना रहा हूं वह भविष्य में चलकर इसके योग्य न होगा, अल्लाह ऐसी बातों से पनाह में रखे।

और आख़िरत आपके लिए दुनिया से बहुत अच्छी है।

अर्थात् आपकी पिछली हालत पहली से बहुत बढ़िया है। वह्यी की यह कुछ दिनों की रुकावट आपके पदच्युत होने का कारण नहीं, बल्कि अधिक से अधिक उन्नति और तरक्क़ी का कारण है और अगर पिछली दशा का विचार किया जाये, अर्थात् आख़िरत की शान और बड़प्पन का जब आदम की तमाम औलाद आपके झण्डे के नीचे इकट्ठी होगी, तो वहां का बड़प्पन और सम्मान और बड़प्पन के असीम दर्जे से बढ़कर है।

अल्लाह बेहतरीन रिज़्क देने वाला है

एक शख़्स का एक गुलाम था जो बहुत मेहनती और ईमानदार था इस की मां, बीवी और बच्चे भी इसके साथ थे, एक दिन वह काम पर न आया तो इसके मालिक ने सोचा कि मुझे इसकी तंख्वाह में कुछ इज़ाफ़ा कर देना चाहिये, ताकि वह दिलजमई से काम करें और आईन्दा गायब न हो, अगले दिन इसकी मुक़र्ररह तनख्वा से कुछ ज़्यादा पैसे इसे दिये जो इसने खामोशी से रख लिये और कुछ न कहा लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह दोबारा गैर हाज़िर हुआ तो इसके मालिक ने गुस्से में आकर इसकी तनख्वाह में किया हुआ इज़ाफ़ा खत्म करने का फैसला किया और अगले दिन इसको फिर पहली वाली तनख्वाह दी। गुलाम ने अब भी ख़ामोशी ही इख़्तयार की और कुछ न कहा तो मालिक ने पूछा! जब मैंने इज़ाफ़ा किया तो तुम ख़ामोश रहे और जब कमी की तो फिर भी ख़मोश हो क्यों? गुलाम ने जवाब दिया, जब मैं पहले दिन गैर हाज़िर था तो इसकी वजह बच्चे की पैदायश थी और आप की तरफ से तनख्वा में इज़ाफे को मैंने वह रिज़्क ख़्याल किया जो वह अपने साथ लेकर आया था जब मैं दूसरी बार गैर हाज़िर हुआ तो इसकी वजह मेरी मां की वफ़ात थी और आपकी तरफ से तंख्वाह को मैंने वह रिज़्क ख़्याल किया जो वह साथ वापस ले गई फिर मैं इस रिज़्क के लिये क्यों परेशान हूं जिसका ज़िम्मा अल्लाह ने उठाया हुआ है।

पंजाब : सिद्धू ने शुरू की बैटिंग तो घिर गए कैप्टन

पंजाब में पिछले कई दिनों से राजनीति पूरे उफान पर रही है। जिन मुद्दों को आधार बनाकर कांग्रेस ने वर्ष 2017 में सत्ता संभाली थी अब नवनियुक्त प्रधान उन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं और सरकार को अपने कार्यकाल की अंतिम छमाही में यह मुद्दे पुरे करने पड़ रहे हैं। पंजाब में लम्बे समय से हाशिए पर बैठे टकसाली कांग्रेसी जहां अब सामने आ गए हैं वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह व सुनील जागखड़ से नाराज़ चल रहे कांग्रेसियों को भी सिद्धू के रूप में नया विकल्प मिल गया है।

नवजोत सिद्धू पंजाब कांग्रेस प्रधान बनने के बाद से ही आक्रामक रुख़ अपनाए हुए हैं। ताजपोशी के बाद से ही सिद्धू लगातार पंजाब में अपनी ही पार्टी को घेरने में लगे रहे। पंजाब में वर्ष 2017 के दौरान हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहिब हाथ में लेकर नशा तस्करों के ख़िलाफ़ एक माह में कार्रवाई करने समेत कई बड़-बड़ी घोषणाएं की थी।

सत्ता में आने के बाद इनमें से किसी भी घोषणा पर ठोस काम नहीं हुआ। जिसके कारण अमरिंदर विपक्षी आम आदमी पार्टी के साथ अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर भी आ गए। अब हाल ही में कांग्रेस द्वारा पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन करने के बाद फिर से चुनावी मुद्दे हावी हो गए हैं। पंजाब में विपक्षी दल आम आदमी पार्टी लंबे समय से बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। पंजाब में महंगी बिजली और इसकी उपलब्धता को लेकर अमरिंदर घिरे हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में चुनावी पारी शुरू करते हुए पहली गारंटी दिल्ली की तर्ज़ पर मुफ्त व सस्ती बिजली देने की दी है। दूसरी ओर अकाली दल का दावा है कि उसके शासन में पंजाब बिजली उत्पादन भरपूर था। इस बीच कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अमरिंदर सिंह पर अकाली सरकार के समय हुए बिजली खरीद समझौते रद्द करने को लेकर दबाव बनाया। जिसके कारण दबाव में आए अमरिंदर ने मजबूरन पिछली अकाली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए बिजली खरीद समझौतों को रद्द करने और नए सिरे से समीक्षा करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बिजली समझौते रद्द किए जाने के बाद अमरिंदर सिंह तो चुप हैं लेकिन आम आदमी पार्टी और नवजोत सिंह सिद्धू इसे अपनी जीत क़रार दे रहे हैं। सिद्धू के दबाव में किए गए इस फैसले ने विपक्षी दलों से बड़ा मुद्दा छीन लिया है।

पंजाब में सरकारी कर्मचारी जहां अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं कच्चे कर्मचारी अमरिंदर को चुनाव के समय पक्का किए जाने का वादा याद दिलाते हुए धरने दे रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कर्मचारियों का समर्थन करते हुए अमरिंदर को लिखे पत्र में उन्हें पक्का करने की मांग

बाक़ी पेज 11 पर

राजस्थान, हिमाचल और मिजोरम में बुज़ुर्गों का जीवन सबसे अच्छा

देश में बुज़ुर्गों को सबसे अच्छा जीवन जीने का अवसर राजस्थान दे रहा है। वहीं, बुज़ुर्गों की कम आबादी वाले राज्यों में से हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है। पूर्वोत्तर के राज्यों में मिजोरम सर्वश्रेष्ठ पाया गया है। केन्द्र शासित प्रदेशों में जहां चंडीगढ़ सबसे आगे रहा, वहीं दिल्ली को अंडमान निकोबार से भी पीछे स्थान मिला। यह दावा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी की गई ताजा रिपोर्ट में किया गया है।

रिपोर्ट को जारी करने वाली परिषद के अध्यक्ष डॉ॰ बिबेक देबरॉय के अनुसार बुज़ुर्गों के जीवन स्तर को मापने के लिए इंस्टीटयूट फॉर कंपीटीटिवनेस द्वारा विभिन्न मानकों के इंडेक्स बनाए गए। इनका लक्ष्य उनके जीवन से जुड़े ऐसे का केन्द्र नहीं रहे हैं। इनमें राज्यवार बुज़ुर्ग होती आबादी का पैटर्न, उनकी दिक्क़तों आदि को समझा गया। वित्तीय, सामाजिक, स्वास्थ्य और आय के ज़रिए जीवन के स्तर को निर्धारित किया गया।

किस राज्य का कितना स्कोर

50 लाख से अधिक बुज़ुर्ग आबादी वाले राज्य

राजस्थान	54.61
महाराष्ट्र	53.31
बिहार	51.82
तमिलनाडु	47.93
मध्य प्रदेश	47.11
कर्नाटक	46.92
उ॰ प्रदेश	46.80
आंध्र प्रदेश	44.37
पं॰ बंगाल	41.01
तेलंगाना	38.19

50 लाख से कम बुज़ुर्ग आबादी वाले राज्य

हिमाचल	61.04
उत्तराखंड	59.47
हरियाणा	58.16
ओडिशा	53.95
झारखंड	53.40
गोवा	52.56
केरल	51.49
पंजाब	50.87
छत्तीसगढ़	49.78
गुजरात	49.00

पूर्वोत्तर के राज्य

मिजोरम	59.79
मेघालय	56.00
मणिपुर	55.71
असम	53.13
सिक्किम	50.82
नागालैंड	50.77
त्रिपुरा	49.18
अरुणाचल	39.28

केन्द्र शासित प्रदेश

चंडीगढ़	63.78
दादर,नगर	58.58
अंडमान नि.	55.54
दिल्ली	54.39
लक्षद्वीप	53.79
दमन/दीव	53.28
पुडुचेरी	53.03
ज.कश्मीर	46.16

उत्तर प्रदेश : सरकार बनाने का स्वप्न किस आधार पर देख रही है कांग्रेस

प्रियंका गाँधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किस आधार पर करती हैं, कोई नहीं जानता। पार्टी महासचिव होने के नाते उनका सबसे ज़्यादा ध्यान बेशक देश के इस सबसे बड़े राज्य पर है लेकिन 1989 के बाद राज्य की सत्ता से बेदख़ल हुई देश की सबसे पुरानी पार्टी अपना वनवास खत्म होने का इंतज़ार कर रही है। केन्द्र की यूपीए सरकार का 2004 से 2014 तक नेतृत्व करने के बाद भी उत्तर प्रदेश में पार्टी के दिन नहीं फिरे। हां, लोकसभा चुनाव में 2009 में उत्तर प्रदेश में 20 सीटें जीतने के बाद ज़रूर पार्टी ने सबको हैरान किया था लेकिन 2012 के विधान सभा चुनाव में पार्टी ने अपने इस प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाई।

जिन राज्यों में मुक़ाबला दो पार्टियों के बीच है, वहां तो ज़रूर कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर ख़ुद को पेश कर पाती है पर उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे उन प्रदेशों में जहां क्षेत्रीय दल भी अपना दबदबा रखते हैं, कांग्रेस के उभार की संभावना कम नज़र आती है। उत्तर प्रदेश में तो पार्टी का नेतृत्व विधानसभा चुनाव 1996 से ही ही दुविधा ग्रस्त रहा है। पहली बार 1996 में ही कांग्रेस ने बसपा के साथ तालमेल किया था। अविभाजित सूबे की 425 में से 300 सीटों पर बसपा लड़ी थी और 125 पर कांग्रेस। गठबंधन का यह प्रयोग अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया था। बसपा 67 और कांग्रेस 33 सीटों पर सिमट गई थी।

बसपा के साथ गठबंधन नाकाम साबित हुआ तो पार्टी ने ऐकला चलो की रणनीति अपना ली। लेकिन उभार कभी भी नहीं हो पाया। जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सभी संसद में जिस सूबे की नुमाइदंगी करते रहे हैं, वहीं पार्टी की पिछले विधानसभा चुनाव में इतनी बुरी गत हुई कि उसे महज़ सात सीटों पर ही सफलता मिल पाई। जब यह चुनाव उसने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ा था।

उत्तर प्रदेश में यह मानने वाले कांग्रेसी नेताओं की अभी भी कमी नहीं है, जिन्हें लगता है कि राहुल गांधी का दूसरे दलों ने पप्पू कहकर भले मज़ाक उड़ाया हो, पर प्रियंका गांधी में उन्हें इंदिरा गांधी की झलक नज़र आती है। प्रियंका ने कहा भी था कि वे दिल्ली छोड़ अब लखनऊ में ही रहेंगी। पर ऐसा हुआ नहीं। तभी तो विपक्षी मज़ाक उड़ाते हैं कि राहुल और प्रियंका तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए आते हैं, वे सियासत को लेकर गंभीर नहीं है। कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी भ्रमित है। वह तय नहीं कर पा रही है कि किसी के साथ गठबंधन करेगी या फिर अकेले मैदान में उतरेगी। पार्टी का जनाधार भी लगातार नीचे आ रहा है। पिछले चुनाव में सपा से गठबंधन के बावजूद उसे 6. 25 प्रतिशत वोट ही हासिल हुआ था। दरअसल लोकसभा चुनाव ने उसे और रसातल में पहुंचा दिया। पार्टी के प्रधानमंत्री पद के चेहरे राहुल गांधी खुद अमेठी में स्मृति ईरानी से हार गए। रायबरेली में सोनिया गांधी की जीत का अंतर भी घटा। यह स्थिति तो तब रही जबकि सपा/बसपा ने इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे।

जिन सात सीटों पर पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में सफलता मिली थी। उनमें दो-दो सहारनपुर व रायबरेली जिले की और एक-एक कानपुर, प्रतापगढ़ व कुशीनगर की थी। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में तो पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया था। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र के दोनों विधायक राकेश सिंह और अदिति सिंह भी कई साल से बग़ावत कर भाजपा के सुर में सुर मिला रहे हैं। कुशीनगर के विधायक अजय कुमार उर्फ लल्लू को पार्टी ने इस उम्मीद से सूबेदार बनाया था कि वे इसमें अपने जोश से प्राण फूंक देंगे। अगर धरातल पर संघर्ष की बात करें तो लल्लू ने मेहनत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मेरठ के पार्ट कार्यकर्ता पिंकी चिन्योटी का दावा है कि कोरोना के कारण जब देश में पूर्णबंदी लागू थी तो अपने घरों को लौटने के लिए परेशान राज्य के प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए कांग्रेस पार्टी और लल्लू ही आगे आए थे। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रोहितश्व अग्रवाल कांग्रेस के वफादार नेता रहे हैं। बक़ौल अग्रवाल मज़दूरों का सवाल हो या किसानों का मुद्दे महंगाई का विरोध हो समाज को बांटने वाली सांप्रदायिक नीतियों का विरोध, केवल कांग्रेस पार्टी ही राज्य की योगी सरकार के ख़िलाफ़ जन आक्रोश का चेहरा बनकर सामने दिखी है। सपा और बसपा जैसी सत्ता के दावेदार दल तो साढ़े चार वर्ष तक जन सरोकारों से दूर ही रहे। पर सियासी समीकरण और उभार की बात करें तो अभी तो सत्तारुढ़ भाजपा से नाराज़ मतदाता भी कांग्रेस को गंभीरता से नहीं ले रहे। पार्टी के ज़्यादातर नेता भी सियासी संभावनएं खोजने के लिए भाजपा, सपा और बसपा का रुख़ करने के बारे में गणित लड़ा रहे हैं। ❑❑

इंग्लैंड दौरा : मोहम्मद शमी और बुमराह ने दिलाई भारत को पहली जीत

पुछल्ले क्रम के बल्लेबाज़ मोहम्मद शमी के संघर्षपूर्ण अर्ध शतक और जसप्रीत बुमराह की पारी के बाद गेंदबाज़ों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने दूसरे टेस्ट मैंच में इंग्लैंड को 151 से रौंद दिया। इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने पांच मैच की सीरीज़ में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है।

मैच के पांचवें और अन्तिम दिन भारत ने इंग्लैंड को 272 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में मेज़बान टीम दूसरी पारी में 120 रन से छोटे से स्कोर पर सिमट गई। कप्तान जो रूट ने सर्वाधिक 272 रन बनाए। मेज़बान टीम के आठ बल्लेबाज़ दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने चार, बुमराह ने तीन और इशांत शर्मा ने दो विकेट लिए, और शमी को एक विकेट मिला।

इससे पहले भारत की दूसरी पारी का आकर्षण शमी (नाबाद 56) और बुमराह (नाबाद 34) के बीच नौंवे विकेट के लिए 89 रन की अटूट साझेदारी रही। भारत ने दूसरे सत्र में केवल नौं गेंदें खेली और 12 रन जोड़ दूसरी पारी आठ विकेट पर 298 रन पर घोषित कर दी। भारत ने अपनी पहली पारी में 364 रन बनाए थे जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 391 रन बनाकर 27 रन की बढ़ हासिल की थी। बुमराह और शमी ने इसके बाद नई गेंद संभाली तथा पहले दो ओवरों में दोनों सलामी बल्लेबाज़ों को पवेलियन भेजकर भारत को शानदार शुरुआत दिखाई। बुमराह की गेंद बर्न्स (शून्य) के बल्ले का किनारा लेकर हवा में लहरा गई जिसे सिराज ने कैच किया। शमी ने अगले ओवर में डॉम सिब्ले को विकेट के पीछे केच कराया। तब इंग्लैंड का स्कोर दो विकेट पर एक रन हो गया। हमीद नौ रन पर पगबाध हो गए।

आईपीएल के लिए आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का रास्ता साफ

क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) ने देश के शीर्ष खिलाड़ियों को टी-20 वर्ल्ड कप से पहले अगले माह संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भाग लेने की लिए अनुमति पत्र जारी कर दिया है। भारत में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण मई में आईपीएल को स्थगित कर दिया गया था। बचे हुए 36 मैच 27 दिन के अंदर 19 सितंबर से 15 अक्तूबर तक खेले जाएंगे। सीए ने खिलाड़ियों को अनापत्ति पत्र तब दिया जब अफग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों देशों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ को स्थगित करने की पुष्टि की। यह सीरीज टी-20 वर्ल्ड कप से पहले भारत में होनी थी। वेस्टइंडीज के साथ एक टी-20 त्रिकोणीय सीरीज भी इन तीनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप की तैयारियों का अहम हिस्सा होती और अफग़ानिस्तान बोर्ड के अधिकारी बोर्ड के अधिकारी इसकी मेज़बानी के लिए स्थल हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल चाहते हैं कि दुनिया के प्रमुख खिलाड़ी एकजुट होकर एक ऐसी संरचना पर फैसला करें जिसमें टैस्ट क्रिकेट के भविष्य को बचाने का काम किया जाए और भारतीय कप्तान विराट कोहली को उसका नामित प्रवक्ता बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'टेस्ट स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी कौशल कम उम्र में हासिल करने की आवश्यकता होती है और फिर कड़ी प्रतिस्पर्धा से इसमें सुधार किया जाता है। यह तभी हासिल किया जा सकता है जब टेस्ट खेलने वाले देशों में एक कार्यात्मक विकास प्रणाली हो।'

यह जश्न आलोचकों को जवाब है : सिराज

भारतीय तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज शानदार फार्म में हैं और विकेट लेने के बाद होठों पर ऊंगली रखकर जश्न मनाने के उनके अंदाज़ के पीछे आलोचकों को मुंह बंद रखने का पैग़ाम छिपा है। सिराज ने लॉर्डस पर अपने पहले टैस्ट में चार विकेट लिए। जब उनसे पूछा गया कि वह हर विकेट के बाद मुंह पर उंगली क्यों रखते हैं तो उन्होंने कहा, 'यह आलोचकों के लिए है जो मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते आए हैं। मसलन मैं यह नही कर सकता या वह नहीं कर सकता तो अब मेरी गेंद उन्हें जवाब देगी। यह मश्न का मेरा नया अंदाज़ा है।'

सिराज ने कहा कि वह लगातार अच्छी गेंदबाज़ी पर ज़ोर दे रहे है। उन्होंने कहा 'मैं जब पहली बार रणजी ट्राफी खेला तो भी मेरा यही लक्ष्य था मैं ज़्यादाप्रयोग की रणनीति नहीं अपनाता क्योंकि इससे मेरी गेंदबाज़ी और टीम के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है।

विंडीज की पाक पर एक विकेट से रोमांचक जीत

किंगस्टन : अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ केमार रोच और युवा जेडेन सील्स के बीच 17 रन की अनमोल साझेदारी के दम पर वेस्टइंडीज ने पहले टैस्ट में पाकिस्तान पर एक विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। सील्स ने पहले 55 रन देकर पांच विकेट भी लिए थे। विंडीज ने पाक को दूसरी पारी में 203 रन पर आउट करके 167 रन की बढ़त ली। मेज़बान टीम के तीन विकेट 16 रन पर गिए गए थे जिसके बाद जर्मेन ब्लैकवुड ने अर्धशतक जमाकर टीम को छह विकेट पर 111 रन तक पहुंचाया। आख़िरी सत्र में रोच ने जोशुआ डा सिल्वा के साथ 28 रन की साझेदारी की। इसके बाद सील्स के साथ अहम साझेदारी करके मेज़बान को जीत तक पहुंचाया। रोच ने 30 रन की नाबाद पारी को कैरियर की सर्वश्रेष्ठ पारी बताया। पाक के लिए शाहीन आफरीदी ने चार और हसन अली ने तीन विकेट लिए। इस जीत से विंडीज ने दो टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़ती बना ली है।

'कोलेस्ट्रॉल' की उचित मात्रा का ध्यान रखना आवश्यक

हमें हमेशा से बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज़ है, हालांकि हक़ीक़त थोड़ी अलग है। कोलेस्ट्रॉल शरीर की हर कोशिका में पाया जाने वाला वसा जैसा पदार्थ है। यह शरीर का अनिवार्य हिस्सा है। कौशिक झिल्ली की मज़बूती, हार्मोन से जुड़ी उत्पत्तियों तंत्रिकाओं और मस्तिष्क के विकास के लिए इसकी ज़रूरत होती है। यह शरीर में हार्मोन, विटामिन डी और खाना पचाने में मददगार पदार्थों का निर्माण भी करता है।

हमें जितने कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है, वह शरीर में ही बनता है, लेकिन तय सीमा से ज़्यादा मात्रा में बनने पर ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और रक्त नलिकाओं में जमा हो जाता है। इनसे धमनियों का मार्ग संकरा हो जाता है जिसे एथरोस्लेरोसिस कहते हैं, इससे कोरोनरी आर्टरी डिसीज (सीएडी), मस्तिष्क पक्षाघात और बाह्या नाड़ी रोग का ख़तरा बढ़ जाता है।

कोलेस्ट्रॉल छोटे-छोटे पैकेज में रक्त की धारा के साथ तैरता हैं, इन्हें लिपोप्रोटीन कहा जाता है ये पैकेज भीतर की तरफ वसा या फैट (लिपिड) से और बाहर की तरफ प्रोटीन से बने होते हैं। कम घनत्व वाले कोलेस्ट्रॉल, जिन्हें लॉ डेनसिटी लिपोप्रोटीन (एलडीएल) कहा जाता है, रक्त वाहिकाओं में जमा हो जाते हैं जबकि ज़्यादा घनत्व या हाइडेनसिटी लिपोप्रोटीन (एचडीएल) को 'अच्छा कोलेस्ट्रॉल' कहा जाता है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को शरीर के दूसरे हिस्सों में वापस लीवर तक ले जाता है और उसे शरीर से बाहर कर देता है।

हर 29 में से तीन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की कोई न कोई गड़बड़ी होती है। लेकिन इनका कोई लक्षण नहीं होता और सिर्फ नियमित जांच से ही इनका पता लगाया जा सकता है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ गया है। कुल मिलाकर खून में एलडीउल कोलेस्ट्रॉल का स्तर जितना ज़्यादा होगा तो दिल का दौरा पड़ने का ख़तरा भी ज़्यादा होगा और एचडीएल का स्तर जितना ज़्यादा होगा, ख़तरा उतना ही कम होगा।

खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर खान पान, शारीरिक सक्रियता और वज़न पर निर्भर करता है। कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फै वाला खाना सीमित मात्रा में खाना चाहिए और मोनो और पॉलीअनसेचुरेटेड फैटअ (पीयूएफए) वाले पदार्थ, जेसे सैफ्लॉवर और फिश ऑयल ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए।

सूखे मेवे का सेवन करें

सूखे मेवे भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक घटा देते हैं। सैचुरेटैड फैट कुछ मांसाहारों, डेयरी उत्पादों चॉकलेट, बेक्ड वस्तुओं, अधिक तेल में तले हुए और प्रसंस्करित आहारों और नारियल तेल जैसे कुछ तेलों में पाया जाता है। हमारे खान-पान में यही वे चीजें हैं जो एलडीएल के स्तर को सबसे ज़्यादा बढ़ाती हैं। ट्रांस फैटस कुछ तले हुए, बेक्ड और प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। ये आपके शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं और एचडीएल यानि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं।

आनुवंशिकता, उम्र जैसी कुछ बातों पर तो ख़ैर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल कई बार खानदान की विरासत में मिलता है , क्योंकि यह देखा गया है कि मेटाबॉलिक गड़बड़ियां मुख्य रूप से आनुवांशिक कारणों से होती हैं। इतना ही नहीं, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, एलडीएल का स्तर भी बढ़ता जाता है। 55 साल की उम्र से पहले एलडीएल का स्तर महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कम होता है, लेकिन 55 की उम्र के बाद उनमें एलडीएल का स्तर पुरुषों की तुलना में ज़्यादा हो सकता है।

करना क्या है आपको

हर तीन महीने में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाकर कोलेस्ट्रॉल लेवल जांचें।

कोलेस्ट्रॉल को क़ाबू में रखने वाला खान पान ही लें।

जिन भी चीज़ों में सैचुरेटेड फैट पाए जाते हैं उन्हें कम से कम खाएं, मसलन कुछ मांस, डेयरी और बेक्ड प्रोडक्ट।

घुलनशील फाइबर से भरपूर जई का दलिया, सेब, नाशपाती सरीखी चीज़ें ज़्यादा खाएं, ये पाचन तंत्र को कोलेस्ट्रॉल सोखने से रोकती हैं।

प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट नियमित कसरत से शरीर के वज़न को क़ाबू में रखें। ❑❑

शेष.... प्रथम पृष्ठ

आया तो जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़ और एम.आर. शाह की पीठ ने लिचोबाम की तुरंत रिहाई के आदेश में कहा कि हम ऐसे व्यक्ति को एक दिन के लिए भी जेल में नहीं रख सकते। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह फैसले के दिन ही पांच बजे से पहले बंदी की रिहाई के आदेश का पालन सुनिश्चित करे। नि:संदेह लिचोबाम की पोस्ट में गरिमा का अभाव था, क्योंकि वह कोरोना के शिकार हुए एक मृतक के विषय में थी, लेकिन क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के उल्लंघन में गिनी जा सकती थी।

इसके बाद कावड़ यात्रा का मुद्दा आया, जिस पर अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया। कावड़ यात्रा में श्रद्धालु अमूमन हरिद्वार से गंगाजल लेकर सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा पर अपने गंतव्य तक जाते हैं और वहां शिव मंदिर में गंगाजल से अभिषेक के साथ यह यात्रा सम्पन्न होती है। गत वर्ष कोरोना के कारण यात्रा प्रतिबंधित हो गई थी हालांकि इस बार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ने यात्रा की अनुमति के शुरूआती संकेत दिए। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसे लेकर उत्तराखंड सरकार हीलाहवाली ही करती दिखी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को दख़ल देना पड़ा। जस्टिस आर.एफ. नरीमन और बी.आर. गवाई ने इस मसले को उठाकर उत्तर प्रदेश सरकार से पुर्नविचार के लिए कहा। इस पर पीठ ने यही कहा कि भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य और अनुच्छेद-21 में उल्लिखित जीवन का अधिकार सर्वोपरि है। न्यायाधीशों ने कहा कि जीवन का अधिकार सबसे बुनियादी मूल अधिकार है और अन्य सभी भावनाएं इसके समक्ष गौण है। उन्होंने कहा कि महामारी ने सभी को प्रभावित किया है और अनुच्छेद 21 ही सभी को संरक्षा प्रदान करता है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्णय पर पुनर्विचार के लिए समय दिया। राज्य सरकार भी तुरंत लाइन पर आ गई और उसने यात्रा रद्द करने का ऐलान किया। इस बीच अदालत के समक्ष एक और मसला आ गया। यह केरल से जुड़ था, जहां राज्य सरकार ने बकरीद से पहले बंदिशों में कुछ छूट दी थी ताकि लोग त्योहार की खरीदारी कर सकें। अदालत ने महामारी के दौर में रियायतें देने को लेकर दबाव के आगे झुकी सूबे की सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही चेताया भी कि इन रियायतों के कारण राज्य में महामारी का प्रसार हुआ तो संबंधित निर्णय लेने वालों के ख़िलाफ़ अदालत कार्रवाई करेगी।

कुछ दिन पहले अमेरिकन बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस चंद्रचूड़ ने नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और दायित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आतंक विरोधी क़ानूनों सहित आपराधिक क़ानूनों का नागरिकों द्वारा की गई आलोचना को दबाने या उनके उत्पीड़न में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां कार्यकारी और विधायी क़दमों से नागरिकों के मूल मानवाधिकारों का उल्लंघन हो वहां संविधान के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट को आगे आना होगा।

कुछ दिन पहले एक अन्य कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने भी इस संदर्भ में कहा कि विद्वानों के अनुसार कोई क़ानून तब तक कानून के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता जब तक कि वह न्याय और समानता के सिद्धांतों से आबद्ध न हो। 'सशक्त स्वतंत्र न्यायपालिका' के महत्व पर ज़ोर देते हुए जस्टिस रमना ने कहा कि न्यायपालिका को ही यह ज़िम्मेदारी मिली है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जो क़ानून प्रवर्तित किए जा रहे हैं क्या वे संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। ऐसे में क़ानूनों की न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका के मुख्य कार्यों में से एक है। रमना ने आगे यह भी कहा, 'न्यायपालिका के महत्व से हमें उस तथ्य को अनदेखा नहीं करना चाहिए कि संविधानवाद के संरक्षण का दायित्व केवल अदालतों के ही ज़िम्मे है। राज्य व्यवस्था के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों संवैधानिक भरोसे के बराबर भागीदार हैं।' ऐसे आदेशों और टिप्पणियों से शीर्ष अदालत का मंतव्य एकदम स्पष्ट है। वह यही कि जो भी उच्चतम न्यायपालिका के नए मिजाज़ को भांपने में नाकाम रहेगा, उसे देर सबेर उसकी तपिश तो झेलनी ही पड़ेगी।

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

है लेकिन ऐसा लग रहा था कि भारत खर्राटे खींच रहा है जबकि पाकिस्तान अपनी गोटियां बड़ी उस्तादी के साथ खेल रहा है। एक ओर वह ख़ून-ख़राबे का विरोध कर रहा है और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई और अशरफ़ ग़नी के समर्थक नेताओं का इस्लामाबाद में स्वागत कर रहा है तथा दूसरी ओर वह तालिबान की तन, मन, धन से मदद में जुटा हुआ है, बल्कि ताज़ा ख़बर यह है कि अब वह क़ाबुल में एक कामचलाऊ संयुक्त सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की बोलती बिल्कुल बंद है। वह तो अपने डेढ़ हज़ार नागरिकों को भारत भी नहीं ला सका है। वह सुरक्षा परिषद् का अध्यक्ष है लेकिन वहां भी उसके नेतृत्व में सारे सदस्य ज़बानी जमा ख़र्च करते रहे। मेरा सुझाव था कि अपनी अध्यक्षता के पहले दिन ही भारत को अफग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की एक शांति सेना भेजने का प्रस्ताव पास करवाना चाहिए था। यह काम वह अभी भी करवा सकता है।

कितने आश्चर्य की बात है कि जिन मुजाहिदीन और तालिबान ने रूस और अमेरिका के हज़ारों फौजियों को मार गिराया और उनके अरबों-ख़रबों रुपयों पर पानी फेर दिया, वे तालिबान से सीधी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार की अपंगता और अकर्मण्यता आश्चर्यजनक है। मोदी को पता होना चाहिए कि 1999 में हमारे अपहृत जहाज को कंधार से छुड़वाने में तालिबान नेता मुल्ला उमर ने हमारी सीधी मदद की थी। प्रधानमंत्री अटलजी के कहने पर पीर गैलानी से मैं लंदन में मिला, वाशिंगटन स्थिति तालिबान राजदूत अब्दुल हकीम मुजाहिद और कंधार में मुल्ला उमर से मैंने सीधा संपर्क किया और हमारा जहाज़ तालिबान ने छोड़ दिया।

तालिबान पाकिस्तान के प्रगाढ़ ऋृणी हैं लेकिन वे भारत के दुश्मन नहीं है। उन्होंने अफग़ानिस्तान में भारत के निर्माण कार्य का आभार माना है और कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताया है। हामिद करज़ई और डॉ. अब्दुल्ला हमारे मित्र हैं। यदि वे तालिबान से सीधे बात कर रहे हैं तो हमें किसने रोका हुआ है? अमरीका ने अपनी शतरंज ख़ूब चतुराई से बिछा रखी है, लेकिन हमारे पास दोनों नहीं है, न शतरंज, न चतुराई! ❑❑

शेष....तालिबान के अफ़ग़ानिस्तान पर....

इतिहास शायद ही किसी देश की तक़दीर इतने अजीबो-ग़रीब तरीके से वक़्त के पन्ने पलटता हो, जितना अफग़ानिस्तान की पहाड़ी पथरीली ज़मीन ने देखी है। कभी रूस के समर्थन से चले रहे ज़हीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा अफग़ानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के मध्ययुगीन शासन को भी देख चुका है।

इसके बाद 9/11 के हमले के बाद अमेरिका और नाटो सेना ने तालिबान के शासन से मुक्ति दिलाई तो 20 साल में अपने पैरों पर खड़ा होने देश सीख ही रहा था कि तालिबान ने फिर सिर उठा लिया।

अप्रैल 2021 में अमेरिका ने ऐलान किया कि सितंबर तक उसके सैनिक लौट जाएंगे। इसके बाद तालिबान ने अमले तेज़ किया और आज नतीजा सबके सामने है।

जहां-जहां तालिबान का कब्ज़ा होता गया, वहां फिर वही शरीया क़ानून लागू हो गया, इस समय पूरे अफग़ानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है, आगे की रणनीति के लिए बैठकें के दौर चल रहे हैं। कई देश तालिबान के समर्थन में हैं तो कई देशों ने तालिबान को मान्यता देने का फिलहाल विरोध किया है। ❑❑

उपभोक्ता कोर्ट में ख़ाली पदों को भरने के लिए मुहुर्त निकालना पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग व राज्यों में उपभोक्ता अदालतों में ख़ली पड़े पदों को न भरने पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराज़गी ज़ाहिर की है। जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश राय की पीठ ने केन्द्र व राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा, 'क्या ख़ाली पदों को भरने के लिए कोई शुभ मुहुर्त निकालना पड़ेगा। लोगों को उम्मीद रहती है कि उनकी शिकायतों का जल्द निवारण होगा। इस उम्मीद को मत डूबोइए। हम ख़ाली पदों पर नियुक्तियाँ चाहते हैं। केन्द्र ने सभी राज्य उपभोक्ता अदालतों में ख़ाली पड़े सभी पदों को आठ सप्ताह के भीतर भरें।' पीठ ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 44 को दो सप्ताह के भीतर नोटिफाई करें। अगर राज्यों ने उपभोक्ता अदालतों में ख़ाली पदों को भरने का विज्ञापन नहीं निकाला तो दो सप्ताह के भीतर विज्ञापन निकालें। अगर राज्यों ने उपभोक्ता अदालतों में ख़ाली पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन नहीं किया है तो चार सप्ताह के भीतर इसका गठन करें। कोर्ट ने कहा, अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो केन्द्र के अफसरों और राज्य के मुख्य सचिवों को तलब करेंगे। केन्द्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलीसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा, 'नियुक्तियों की शर्त ट्रिब्यूनल रिफार्म एक्ट 2021 के अनुसार है। जस्टिस कौल ने कहा, जब किसी को कुछ करना होगा तो भ्रम नहीं होना चाहिए। इससे पहले न्यायमित्र आदित्य नारायण ने बताया था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में सात में से केवल चार पर भरे हैं। इस पर जस्टिस कौल ने पूछा बाकी क्यों नहीं भरे गए। जस्टिस कौल ने कहा कि -आप लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के इच्छुक नहीं है तो उम्मीद भी मत जगाइए।

गुजरात हाईकोर्ट ने 'लव जिहाद' कानून की कई धाराओं पर लगाई रोक

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को 'गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधित) अधिनियम-2021' की कुछ धाराओं के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस अधिनियम को 'लव जिहाद' के नाम से भी जाना जाता है। अदालत ने तीसरे शख्स द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि यह तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि लड़की को झूठा या किसी साजिश के तहत फंसाया गया है। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने शादी के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाए गए संशोधित कानून की कई धाराओं पर रोक लगा दी है। जिन धाराओं पर लगाई गई है, उनमें वह भी शामिल हैं, जिनमें अंतधार्मिक विवाह को जबरन धर्मांतरण का कारण बताया गया है। बता दें कि इस कानून में जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में कुछ ऐसे कठोर प्रावधान किए गए हैं, जिनकी वजह से दोषी साबित किए गए व्यक्ति को कड़ी सजा दी जा सकती है।

शेष.... 20 वर्ष बाद इतना मज़बूत...

बाइडेन के ऐलान के बाद तालिबान ने मोर्चा खोल दिया और 90 हज़ार लड़ाके वाले तालिबान ने 3 लाख से अधिक अफग़ान फौजों को सरेंडर को मजबूर कर दिया। अफग़ान राष्ट्रपति अशरफ़ गनी उनके प्रमुख सहयोगी, तालिबान से लड़ रहे प्रमुख विरोधी कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम और कई वॉर लॉर्डस देश छोड़कर चले गए हैं। इस समय तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान में अपना कब्ज़ा जमा चुके हैं। ❑❑

शेष.... सिद्धू ने शुरू की बैटिंग...न

उठाई। अमरिंदर सिंह ने सिद्धू की इस मांग को पूरा करते हुए उन्हें कैबिनेट कमेटी का गठन कर दिया है। जिसकी बैठक में सभी विभागों के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के बाद में फेसला किया जाएगा। अपनी ही सरकार को मुश्किल में डाल रहे नवजोत सिद्धू जहां कांग्रेस आलाकमान द्वारा किए गए 18 सूत्रीय एजेंडे को लागू करवाने के लिए सक्रिय हो गए हैं वहीं उन्होंने अमरिंदर सरकार दलितों के हित में बड़ा फैसला करने, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर राज्य स्तर पर कृषि क़ानूनों को रद्द करने की मांग कर चुके हैं। जिसके कारण अमरिंदर को मजबूरी में आगामी सत्र के दौरान दलित कल्याण बिल पास करने का ऐलान करना पड़ गया है। अब नवजोत सिंह सिद्धू गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने, मादक पदार्थ तस्करी के मामले में एसटीएफ की पहली रिपोर्ट में आरोपी क़रार दिए गए नशा कारोबार के सरगना के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। सिद्धू की इस मांग को लेकर अमरिंदर सिंह दुविधा में फंसे हुए हैं। जिस पर आने वाले दिनों में फैसला लिया जाएगा।

बहरहाल नवजोत सिंह सिद्धू जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों पर अमरिंदर सिंह बुरी तरह से घिर गए हैं। अमरिंदर सिंह अगर सकारात्मक कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पंजाब की जनता के सामने नवजोत सिंह सिद्धू मजबूत हो जाएंगे और विपक्ष के हाथों से मुद्दे निकलने से सिद्धू को मज़बूती मिल रही है। अमरिंदर सिंह अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो विपक्ष के साथ उन्हें अपनी ही पार्टी के प्रधान के निशाने पर आना पड़ सकता है। पांच वर्ष पहले चुनाव के समय किए गए वादों को साढ़े चार साल तक पूरा नहीं करने और अब कांग्रेस प्रधान के दबाव में पूरा करने को लेकर अमरिंदर सिंह दबाव में हैं। ❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **15 Aug.2021** Posting Days : **MON. - TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

मंज़र पस-मंज़र वेद प्रताप वैदिक

•रोज़गार की सूरत•ख़तरा और नज़दीक

•काबुल : भारत की बोलती बंद क्यों?

रोज़गार की सूरत

पिछले करीब डेढ़ वर्ष से देश में वैश्विक महामारी की वजह से लगाई गई पूर्णबंदी के हालात में सबसे ज़्यादा मार रोज़गार पर ही पड़ी है। कई अध्ययनों में यह बताया गया है कि विशेषकर शहरों में बेरोज़गारी के आंकड़ों में चिंताजनक बढ़ोत्तरी हुई। लेकिन बहुत सारी गतिविधियां ठप रहने के बीच शायद इसकी सही तस्वीरें अब तक सामने नहीं आ सकी है और इसके नुकसानों का आंकलन नहीं हो सका है। इसी के मद्देनज़र संसद की एक समिति ने श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय से कहा है कि कोरोना विषाणु से उपजी

एक ओर महामारी से जूझते लोग इसकी वजह से सेहत और जीवन को लेकर फिक्रमंद रहे और दूसरी ओर संक्रमण रोकने के लिए लगाई गई पूर्णबंदी और अन्य उपायों के बीच बाज़ार, उद्योग और संस्थानों के सामने सहजता से काम करना संभव नहीं रहा। जिस क्षेत्र इंटरनेट के ज़रिए कामकाज चल सकता है, उसमें तो घर से काम जैसे विकल्प अपनाए गए, लेकिन प्रत्यक्ष भागीदारी से चलने वाली गतिविधियां पूरी तरह ठप पड़ गईं।

महामारी और उससे पैदा हालात के बीच रोज़गार के नुकसान की सही तस्वीर पेश करे। समिति ने मंत्रालय को विश्वसनीय एजेंसियों के आंकड़ों और अध्ययन का मिलान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि ईपीएफओ के आंकड़ों से करने की सलाह दी, ताकि देशभर में नौकरियों के नुसान की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। समिति की राय इसलिए भी अहम है कि जब तक नुकसान की वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आएगी, तब तक उससे निपटने के लिए ठोस योजना पर भी काम करना मुश्किल होगा।

यह ढंका छिपा नहीं है कि महामारी के चलते समूचे देश में केन्द्र और राज्यों की ओर से लगाए गए अंकुशों के बीच आर्थिक गतिविधियां कई मौक़ों पर बिल्कुल ठप रहीं और संक्रमण की रफ्तार में कमी के साथ कुछ राहत मिलने के बावजूद अब तक यह सामान्य नहीं हो सकी हैं। ऐसे में देशभर में रोज़गार पर बेहद प्रतिकूल असर पड़ा है। एक ओर महामारी से जूझते लोग इसकी वजह से सेहत और जीवन को लेकर फिक्रमंद रहे और दूसरी ओर संक्रमण रोकने के लिए लगाई गई पूर्णबंदी और अन्य उपायों के बीच बाज़ार, उद्योग और संस्थानों के सामने सहजता से काम करना संभव नहीं रहा। जिस क्षेत्र इंटरनेट के ज़रिए कामकाज चल सकता है, उसमें तो घर से काम जैसे विकल्प अपनाए गए, लेकिन प्रत्यक्ष भागीदारी से चलने वाली गतिविधियां पूरी तरह ठप पड़ गईं। इस क्रम में संगठित क्षेत्रों में भी कामकाज और रोज़गार का संतुलन बुरी तरह बिगड़ा। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि असंगठित क्षेत्र में काम करके गुज़र बसर करने वाली कितनी आबादी के सामने कैसी चुनौती खड़ी हो गई होगी। सच्चाई यह है कि बंदी में राहत के बावजूद अब भी आर्थिक गतिविधियां संभलने के क्रम में हैं, लेकिन तीसरी लहर की चेतावनियों के मद्देनज़र फिर से बंदी की आशंका भी लगातार बनी हुई है। एक आंकलन यह ज़रूर है कि संगठित क्षेत्रों से बेरोज़गार हुए बहुत सारे लोगों ने असंगठित क्षेत्रों में काम या फिर स्वरोज़गार के नए विकल्प ढूंढे। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां अभी सीमित दायरे में ही कई चुनौतियों से जूझ रही है तो यह विकल्प भी कितनी दूर का सहारा बन सकता है। यह जगज़ाहिर तथ्य है कि जब तक लोगों की आमदनी सामान्य रहती है, क्रय शक्ति मज़बूत रहती है, तभी तक बाज़ार में खरीद-फरोख़्त की गतिविधि भी सहज रहती है। मगर हालत यह है कि खरीदारी का स्तर केवल अनिवार्य वस्तुओं तक सिमट कर रह गया है और लोग ज़रूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने या टालने लगे हैं। ऐसा शायद इसलिए भी हो रहा है कि भविष्य के प्रति कोई अनिश्चितता नहीं है। संचार माध्यमों में लगातार महामारी की तीसरी लहर के डर की ख़बरें चल रहीं हैं और इस वजह से आम लोगों सहित बाज़ार की भी आर्थिक गतिविधियां भी सीमित जोखिम के आधार पर चल रही हैं। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो इससे बेरोज़गारी की तस्वीर तो और बदतर होगी ही, इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

ख़तरा और नज़दीक

पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट सनसनीखेज़ है। रिपोर्ट में पूरी दुनिया को सीधे तौर पर चेता दिया गया है कि जलवायु संकट से बनने वाले हालात में अब बचने छिपने की जगह भी नहीं मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र ने एक तरह से ख़तरे का सायरन बजा दिया है। यानि अब दुनिया के सामने फौरन बचाव के अलावा कोई चारा दिखता नहीं है। जलवायु संकट को लेकर रिपोर्टें तो पहले भी आती रही हैं लेकिन इस बार की रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली है। वैसे जलवायु संकट पर संयुक्त राष्ट्र ही नहीं, बल्कि देश-विदेशी संस्थान, सरकारी और ग़ैर सरकारी संगठन भी लगातार चेताते रहे हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अंतर-सरकारी पैनल इस इस बार दुनिया को चेतावनी भले अंदाज़ में झकझोरा है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन की गति का जो अनुमान था, उसकी रफ्तार ज़्यादा ही तेज़ हो गई है।

संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी अपनी जगह है लेकिन ग़ौर किया जाना चाहिए कि हाल के दशकों में पृथ्वी के लगभग हर हिस्से पर कुदरत की मार बढ़ती जा रही हैं इस समय दुनिया के कई देशों में जंगल धधक रहे हैं। इससे तो लगता है कि आग की ये लपटें कहीं बहुत जल्दी शहरों को भी लपेटें में न लेने लगें। अमेरिका, कनाडा हो या फिर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देश या फिर तुर्की जैसे देश, जंगलों की आग ने इंसान के सामने गंभीर ख़तरा खड़ा कर दिया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसी तरह हाल में यूरोपिय देशों में आई बाढ़ ने ज़्यादातर देशों का हुलिया ही बदल डाला। कहा तो यह जा रहा है कि पिछले एक हजार साल में यूरोप में ऐसी भयंकर बाढ़ नहीं आई। दुनिया के कई हिस्से बाढ़ और जंगलों की आग से बचे हैं तो वहां सूखे ने क़हर बरपा रखा है और पिछले कुछ साल में तो उन देशों में भी लू ने लोगों को झुलसा दिया जहां लोग गर्मी के मौसम की कल्पना भी नहीं करते थे। फिर वातावरण का तापमान बढ़ने से ध्रुवीय प्रदेशों तक की बर्फ पिघल रही है और समंदरों का जलस्तर उठता जारहा है। ज़ाहिर है, तटीय शहरों और टापुओं को आने वाले समय में डूबने से बचा पाना मुश्किल हो जाएगा।

आमतौर पर हम कहते आए हैं कि अपनी धरती, पानी और हवा के साथ इंसान जिस तरह की क्रूरता करता जा रहा है, उससे प्रकृति भी ख़फा हो चली है और यह सब कुछ एक ही दिन में नहीं हुआ। इसका सबूत यह है कि दुनिया के सारे विकसित और विकासशील देश लंबे समय से इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जलवायु संकट से निपटा कैसे जाए। पर्यावरण और धरती को बचाने के लिए दशकों से दुनिया में छोटे बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, समझौते और संधियां भी होती रही हैं पर ये समझौते अब तक कारगर नहीं दिखे। विद्वान् लोग इसका एक बड़ा कारण यह मानते हैं कि पर्यावरण बचाने के लिए जिन देशों को सबसे ज़्यादा गंभीरता दिखानी थी, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा कोताही बरती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका ही है जो अपने स्वार्थों के चलते पेरिस समझौते से अलग हो गया था। प्रश्न तो यह भी है कि ऐसे कितने देश हैं जिन्होने कार्बन उत्सर्जन घटाने में संजीदगी दिखाई? बहरहाल अब धरती को बचाने का काम सबके सर पर आ गया है तो बेहतर यही होगा कि समर्थ, सम्पन्न देश सबसे पहले सक्रिय हों, और कुछ ऐसा ठोस करके दिखाएं जिससे दूसरे देशों को भी वैसा ही करने की प्रेरणा मिल सके।

काबुल : भारत की बोलती बंद क्यों?

पिछले कई दिनों से मैं बराबर लिख रहा हूं और टीवी चैनलों पर बोल रहा हूं कि काबुल पर तालिबान का कब्ज़ा होने ही वाला है लेकिन मुझे आश्चर्य है कि हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय, हमारा विदेश मंत्रालय और हमारा गुप्तचर विभाग आज तक सोता हुआ क्यों पाया गया है?

कितने आश्चर्य की बात है कि जिन मुजाहिदीन और तालिबान ने रूस और अमेरिका के हज़ारों फौजियों को मार गिराया और उनके अरबों-ख़रबों रुपयों पर पानी फेर दिया, वे तालिबान से सीधी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार की अपंगता और अकर्मण्यता आश्चर्यजनक है। मोदी को पता होना चाहिए कि 1999 में हमारे अपहृत जहाज को कंधार से छुड़वाने में तालिबान नेता मुल्ला उमर ने हमारी सीधी मदद की थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल क़िले से बहुत लंबा-चौड़ा भाषण दे डाला और 15 अगस्त को जिस समय उनका भाषण चल रहा था, तालिबान काबुल के राजमहल (ख़ाके-गुलिस्तां) पर कब्ज़ा कर रहे थे लेकिन ऐसा नहीं लगा कि भारत को ज़रा सी भी उसकी चिंता है। अफग़ानिस्तान में कोई भी उथल पुथल होती है तो उसका सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान और भारत पर होता

बाक़ी पेज 11 पर

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ **Paytm** या **PhonePe** द्वारा **9811198820** पर **SHANTI MISSION**

❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण

SBI A/c **10310541455**
Branch: **Indraprastha Estate**
IFS Code: **SBIN0001187**

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in —— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक शकील अहमद सैयद ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173